राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
लोकशक्ति
RNI Regn. No.7789/1964

मोदी राज में रेलवे का हुआ कायाकल्प, रेल बजट में 30 गुना वृद्धि, हर दिन बिछाई जा रही 15 किलोमीटर ट्रैक

मोदी राज में भारत के ग्रोथ को लेकर भरोसा हुआ और मजबूत: मूडीज ने जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाकर किया 8 प्रतिशत

वर्ष-60 › अंक -76 रायपुर बुधवार 13 मार्च 2024 शुक्लपक्ष विक्रम संवत 2080 पृष्ठ 8 › मूल्य : 2 रू डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

खट्टर के स्तीफे के बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी

नायब सैनी हरियाणा के 11वें सीएम बने :5 मंत्रियों ने शपथ ली, सभी पिछली कैबिनेट में थे; सैनी ने खट्टर के पैर छुए

नईदिल्ली,एजेंसी।

लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है. मनोहर लाल खट्टर ने आज यानी मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया. नायब सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पांच मंत्रियों के साथ शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस संबंध में राजभवन पहुंचे नायब सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी।

शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सैनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. नायब के अलावा कंवरपाल गुज्जर और मूलचंद शर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

विकसित भारत की कल्पना, आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव नहीं : मोदी

एजेंसी।

आज हमने ये जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं के जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है. आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारो दिशाओं में गूंजता ये विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है. आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना है. यही पोखरण है, जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम भी देख रहे हैं. भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है।

लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. विकसित भारत की कल्पना, आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव नहीं है. भारत को विकसित होना है, तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा. इसलिए आज भारत, खाने के तेल से लेकर आधुनिक विमान तक, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है. हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम की जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है. हथियार और गोला-बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम Made In India की उड़ान अनुभव कर रहे हैं. यही तो भारत शक्ति है. बाते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं. हमने नीति-विषयक सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने MSME स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया. आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरीडोर बन रहे हैं. इनमें अब तक 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है. आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्टरी भारत में काम करना शुरू कर चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है. विकसित राजस्थान, विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा।

कुर्सी पर सीएम और जमीन पर दलित डिप्टी सीएम, वीडियो वायरल कर लोग पार्टी को लगा रहे फटकार

एजेंसी।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अन्य मंत्रियों के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उनके दलित डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क जमीन पर बैठे हुए हैं। लोग कांग्रेस के सामाजिक न्याय के नारे पर तंज कसते हुए फटकार लगा रहे हैं। वीडियो में साफदिख रहा है कि दलित डिप्टी सीएम फर्श पर बैठे हुए हैं, जबकि सीएम के साथ अन्य मंत्री ऊपर बैठे हुए हैं। लोग सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर वीडियो को शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने दलित डिप्टी सीएम को फर्श पर बैठाकर दलितों का अपमान किया है।

बापू के आश्रम को बताया अप्रतिम ऊर्जा का केंद्र

मोदी ने किया साबरमती आश्रम के मास्टर प्लान का शुभारंभ

गुजरात को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात

नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली: एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर हैं. मंगलवार को पीएम मोदी ने रेलवे को कई सौगात दीं. पीएम मोदी 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इसके साथ ही 85 हजार करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया. इसके बाद पीएम मोदी महात्मा गांधी के साबरमती स्थित आश्रम पहुंचे. जहां उन्होंने एक पौधा लगाया और आश्रम के कायाकल्प के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया. इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, ÷पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है. हर किसी को जब-जब यहां आने का अवसर मिलता है, तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं. सत्य, अहिंसा का आदर्श हो, राष्ट्र आराधना का संकल्प हो, गरीब और बंचित की सेवा में नारायण सेवा देखने को ख्वाब हो साबरमती आश्रम बापू के इन मूल्यों को आज भी सजीव किए हुए हैं.÷ पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने यहां साबरमती आश्रम पुनर्विकास और विस्तार का शिलान्यास किया. बापू का पहला आश्रम था जो कोचर आश्रम था उसका भी विकास किया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि आज उसका भी लोकार्पण हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि आज 12 मार्च की ऐतिहासिक तारीख भी है. आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई. पीएम मोदी ने कहा कि पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम सदैव अतुल्य ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है. जब भी हम यहां आते हैं तो हम बापू की प्रेरणा को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं.÷

'साबरमती से शुरू हुआ अमृत महोत्सव' - पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कोचरप आश्रम में ही बनाया था. गांधी जी जहां चरखा चलाया करते थे कारपेट्री का काम सीखते थे दो साल तक कोचरप आश्रम में रहने के बाद गांधी जी साबरमती आश्रम में आए थे. पीएम मोदी ने कहा कि आजाद भारत में भी ये तारीख ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर के नए युग का सूत्रपात करने की गवाह बन चुकी है।

बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी जहां मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाया जाता है - मोहन यादव

रायपुर,। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है किभारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां मोहन यादव जैसा सामान्य कार्यकर्ता मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और यदि इससे भी बड़ा उदाहरण देखना है तो नरेंद्र मोदी से बड़ा उदाहरण और क्या होगा। जहां एक चाय वाला विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होता है और ना सिर्फ प्रधानमंत्री बनता है अपितु प्रधानमंत्री के रूप में भारत के गौरव को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाने में अपना सर्वस्व लगा देता है। उक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय के सभागार में रायपुर लोकसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक में कही।

मुख्यमंत्री साय से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सौजन्य मुलाकात

लोकशक्ति। संवाददाता।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने डॉ. यादव का आत्मीय स्वागत किया और शाल एवं बस्तर आर्ट की कलाकृति भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, सांसद श्री सुनील सोनी, श्री संजय श्रीवास्तव और श्री राहुल कोठरी मौजूद थे।

डॉ. मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वे यहां राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत राशि वितरण तथा अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

मॉरीशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति को डॉक्टर ऑफसिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया

एजेंसी। मॉरीशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को डॉक्टर ऑफसिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि मॉरीशस विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ आकांक्षी युवाओं के सपनों की सीढ़ी नहीं हैं; वे ऐसे स्थल हैं जहां मानव जाति के भविष्य का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि वह इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्राप्त करके विशेष रूप से सम्मानित हुई हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सभी युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को अपने अविरल जुनून की खोज करने और अपने सपनों को फ्लीभूत करने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति मुर्मु ने शिक्षा की शक्ति के परिवर्तनकारी प्रभाव के अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा ही है जो हमें असुरक्षा और अभाव से अवसरों और आशा की ओर ले जाती है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भारत को आने वाले कल की 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' में ले जाने के लिए युवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की दूरदर्शी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करके नवाचार का एक पावर हाउस बन जाएगी जो मानवता के कल्याण में वृद्धि करती है।

बिलासपुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी विमान सेवा शुरू

एजेंसी ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकें। आज बिलासपुर वासियों की लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी मांग पूरी हो रही है। बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मेरी ओर से इसके लिए बिलासपुर वासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है। इस हवाई सेवा का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नई हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जगदलपुर के लिए भी खुश खबरी है, आज जगदलपुर से जबलपुर के लिए भी हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। इस हवाई सेवा का लाभ बस्तर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। यहां व्यापार और पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

योगी कैबिनेट में शामिल किए गए नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

एजेंसी।

उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही किए गए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग मिला है। मिली जानकारी के अनुसार, दारा सिंह चौहान को कारागार विभाग मिला है। सुनील शर्मा को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तो अनिल कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आवंटित किया गया है।

धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड विभाग दिया गया है। इन सभी को पिछली पांच मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। अभी हाल में हुआ था मंत्रिमंडल का विस्तार बता दें कि पिछले दिनों सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार करते हुए चार नए मंत्री बनाए थे। इनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान, पुरकाजी से आरएलडी विधायक अनिल कुमार और बीजेपी के साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा शामिल थे। इसके साथ ही योगी सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है।

आर्मी पॉवर | भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन

तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों की गर्जना से गूंजा पोखरण

डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ा

एजेंसी।

पोखरण से पीएम मोदी ने कहा कि भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है। लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की कल्पना, आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव नहीं है। भारत को विकसित होना है, तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। इसलिए आज भारत, खाने के तेल से लेकर आधुनिक विमान तक, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है।'

पीएम मोदी ने बड़े संकेत देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान, विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है।इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इम्पोर्टर हुआ करता था। जबकि आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है।

480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार

एजेंसी। पोरबंदर भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात एटीएस और एनसीबी ने अरब सागर में एक बड़ा अभियान चलाते हुए छह पाकिस्तानी नागरिकों को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा है। एनसीबी के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार पाकिस्तानियों के पास से 480 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद हुई है। सभी को पोरबंदर लगाया गया है। एनसीबी ने इस संयुक्त अभियान के बारे में बताया। अधीक्षक सुनील जोशी ने संयुक्त अभियान के बारे में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के पास अरब सागर में एक संयुक्त अभियान चलाया।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

छत्तीसगढ़ में किसानों के घर हो रही धन वर्षा : मध्यप्रदेश के सीएम

सांसद संतोष ने एमपी के सीएम का किया स्वागत

सांसद संतोष ने लिखा: राजनांदगांव पधारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का संस्कारधानी में स्वागत किया। इन दौरान कृषि उपज मंडी केंद्र, राजनांदगांव में अटल किसान न्याय योजना के तहत किसानों को एमएसपी के बाद धान का अतिरिक्त 917 रुपये उनके खातों में हस्तांतरित की गई।

लोकशक्ति- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ऐसा लग रहा है आज मानों छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारन्टी आज पूरी हुई। किसानों को आदान सहायता देने में छत्तीसगढ़ में जो कार्य हुआ है वह किसी अन्य राज्य में नहीं किया गया है। डॉ. यादव आज राजनांदगांव जिले में कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण और किसान मेला को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सांसद श्री संतोष पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजनांदगांव से वर्चुअल रूप से जुड़कर मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में बालोद में आयोजित राज्य स्तरीय कृषक उन्नति योजना के कार्यक्रम को भी सम्बोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। कृषक उन्नति योजना अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के अंतर की राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों के जीवन में परिवर्तन आयेगा। सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना वादा निभाते हुए महतारी वंदन योजना लागू की है, जिससे महिलाओं को सम्मान मिला है। इससे महिलाओं में अपूर्व उत्साह एवं खुशी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के अंतर की राशि किसानों के खाते में अंतरित की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा आज बालोद में आयोजित कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कर खरीफवर्ष 2023-24 में राज्य के लगभग 24 लाख 72 हजार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के अंतर की राशि 13,320 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में अंतरित की गई। कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के प्रति क्विंटल 917 रूपए के मान से अंतर की राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित की गई।

आईटीएम यूनिवर्सिटी में सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रायपुर. आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर ने यंग इंडिया -कॉन्फेडरेशन ऑफइंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर के बारे में छात्राओं के बीच जागरूकता लाने लिए नया रायपुर स्थित अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम ÷लेट्स लर्न अबाउट सर्वाइकल कैंसर÷ का आयोजन किया। इस सत्र के स्पीकर के रूप में निरामयाः कैंसर फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री सुदेशना रुहान ने छात्राओं और महिला प्राध्यापकों को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, कारण, रोकथाम और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित कई प्रश्न पूछे और रोकथाम के कदमों पर लंबी चर्चा की।

लापरवाही से होती हैं दुर्घटनाएं, इससे बचें : बंजारा

मड़वा विद्युत संयंत्र में राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह में हुए विविध कार्यक्रम

जांजगीर - लापरवाही व अति उत्साह के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए हर व्यक्ति को सजग रहने की जरूरत है। समय पर अपने कार्यों को पूरा करें ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा जा सके। इससे दुर्घटनाएं रूकेंगी। यह विचार राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में कार्यपालक निदेशक एसके बंजारा ने व्यक्त किए। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह (एबीवीटीपीएस) मड़वा में 04 से 10 मार्च तक राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक एसके बंजारा, कार्यक्रम के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रवीण श्रीवास्तव एवं आरके साव की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि विद्युत संयंत्र का संरक्षा विभाग लगातार कर्मचारियों एवं श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। विभाग से मिलने वाली जानकारियों का उपयोग कर संभावित दुर्घटना को टाला जा सकता है।

अधीक्षण अभियंता (संरक्षा) एन. साहा के समन्वय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2024 के लिए संरक्षा थीम- ' ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दें' रखी गई है। ईएसजी (श्वस्त्र) से यहां अर्थ पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन से है।

पूरे सप्ताह कार्यपालन अभियंता (संरक्षा) नरेंद्र कुमार देवांगन, सहायक अभियंता विजय कुमार बर्मन एवं रीना धुरंधर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को संपादित कराया गया। इनमें मॉकड्रिल, सुरक्षा जागरूकता व्याख्यान, सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन, नारा एवं निबंध प्रतियोगिता शामिल हैं। विजयी प्रतिभागियों को कार्यपालक निदेशक एसके बंजारा एवं अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। इनमें संजय बरेठ, चंद्रकांत वर्मा, संतोष सोनी, हेमंत खरे एवं इंदु खलखो शामिल हैं। कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता आरके नायक, वीके सिंह, धमेंद्र बंजारे, एनके घृतलहरे, जनसंपर्क अधिकारी बसंत शाहजीत समेत बड़ी संख्या में विभिन्न वृत्तों के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अधिकारी-कर्मचारी एवं श्रमिक उपस्थित रहे।

शतप्रतिशत नागरिकों का आधार पंजीयन करें : कलेक्टर

मोहला कलेक्टर जयवर्धन की अध्यक्षता में आज आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित आधार सेवा केंद्र के संचालन और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिले का हर एक नागरिक महत्वपूर्ण है और इन सभी नागरिकों का आधार पंजीयन हो, यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी दशा में कोई भी नागरिक आधार पंजीयन से वंचित न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिले के समस्त आधार सेवा केंद्रों के संचालक यह सुनिश्चित करें कि, किसी भी दशा में एक भी फर्जी आधार पंजीयन ना हो, इसके साथ ही किसी भी नागरिक के आधार का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका संवेदनशीलता के साथ पालन किया जाए। किसी आधार पंजीयन का गलत इस्तेमाल किये जाने पर संबंधित आधार सेवा केंद्र के संचालक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय इकाई का अवार्ड

एजेंसी।

राष्ट्रीय चेयरमेन प्रदीप मित्तल के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की 9- 10 मार्च को वृंदावन में संपन्न दो दिवसीय बैठक : प्री वेडिंग सूट पर प्रतिबंध, विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयनका को भारत रत्न देने की मांग, राष्ट्रीय स्तर पर होगा अग्र अलंकरण का आयोजन, लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय।

समापन समारोह में उपस्थित जी नेटवर्क के चैयरमेन सुभाष चंद्रा ने कहा- देशभर में अग्रवाल समाज की राष्ट्रीय संस्थाओं को एकजुट कर दिल्ली में बनाया जाएगा एक शानदार भवन।

राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ.अशोक अग्रवाल एवम् महामंत्री गिरीश मित्तल ने पढ़े सदस्यों से बैठक पूर्व मंगाए गए सुझाव,लिए गए निर्णय ।

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 9 एवं 10 मार्च को धर्म की नगरी वृंदावन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में संपन्न हुई, इस अवसर पर बैठक का शुभारंभ भगवान अग्रसेन जी एवं कुलदेवी महालक्ष्मी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, तत्पश्चात प्रथम दिवस की बैठक में जहां अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के अंतर्गत विभिन्न समितियो का गठन करने पर चर्चा करते हुए निर्णय लिए गए,

बैठक के दौरान द्वितीय दिवस जहां देश के विभिन्न स्थानों के समाज बंधुओ ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे तो वहीं इस दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चैयरमेन प्रदीप मित्तल, मुख्य अतिथि जी नेटवर्क के डॉक्टर सुभाष चंद्रा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आर एन गुप्ता हैदराबाद,राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ रामबाबू सिंघल नईदिल्ली, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल रायपुर, सतीश जैन बेंगलुरु,

राष्ट्रीय महामंत्री द्वय राजेश भरूका सूरत, गिरीश मित्तल नईदिल्ली, प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक संजय गुप्ता, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जितेंद्र सिंघल बागपत, आयोजन समिति के सदस्य महावीर गोयल,सविता गुप्ता, एसके गुप्ता, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री राजेश गुप्ता मौजूद रहे।

द्वितीय दिवस की बैठक का शुभारंभ सुबह 10:00 बजे हुआ जिसमें द्वितीय दिवस के कार्यक्रम में ' न्यूज़ के चैयरमेन डॉक्टर सुभाष चंद्रा प्रमुख रूप से मौजूद थे एवं इस दौरान जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सहयोग करने वाले सभी सदस्यों का एवं स्वागत समिति के सदस्यों का स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया, तथा बैठक के दौरान अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल रायपुर ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से ज़ी न्यूज़ के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भगवान अग्रसेन जी के फोटो युक्त चांदी के सिक्के भेंट किये, तो वहीं आगंतुक सभी सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए एवं कार्यक्रम का संचालन करते हुए राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल एवं आयोजन समिति के सदस्य गिरीश मित्तल ने समाज बंधुओ द्वारा दिए गए लगभग 50 प्रस्ताव पर वन टू वन चर्चा की, जिसमें विभिन्न प्रस्तावो को स्वीकृति प्रदान की गई तथा इन सभी प्रस्तावों पर आने वाले चेन्नई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विस्तार पूर्वक गति देने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जी न्यूज़ के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि पूरे देश भर में अग्रवाल समाज के सभी संगठनों को एकजुट किया जाएगा तथा भारत सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में अग्रवाल समाज के बड़े भवन निर्माण के लिए जो जमीन अग्रोहा विकास ट्रस्ट को दी है,उस भूमि पर सभी समाज बंधुओ के लिए,आवश्यकता अनुरूप निर्माण किया जाएगा, यह निर्माण अग्रवाल समाज के मुख्य संगठन अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन और अग्रोहा विकास ट्रस्ट के साथ-साथ अन्य सभी राष्ट्रीय संगठनों को साथ लेकर किया जाएगा।

बैठक के दौरान उपस्थित विभिन्न राज्यों से पहुंचे सदस्यों ने आने वाले तीन माह में 5 लाख नए सदस्य बनाने का भी लक्ष्य लेकर अपना संकल्प लिया, वहीं कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के संस्थापक प्रदीप मित्तल ने नए राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में दिल्ली के गिरीश मित्तल की नियुक्ति की तथा गिरीश मित्तल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर सभी उपस्थित सदस्यों ने उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी, बैठक में अग्र अलंकरण की योजना को एक माह में प्रस्तुत करने के लिए, राष्ट्रीय संयोजिका के रूप में डॉक्टर अनीता मोहनलाल अग्रवाल रायपुर को नियुक्त किया गया, बैठक का सुंदर आतिथ्य अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से किया गया तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम वृंदावन मथुरा में बहुत ही सुंदर ढंग से आगंतुकों के संपूर्ण व्यवस्था की गई,तथा आयोजन को सफल बनाने में पूरी टीम जुटी रही एवं अंत में सभी का आभार प्रदर्शन किया गया, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की इस दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश से वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल रायपुर,छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के अध्यक्ष नेतराम अग्रवाल भिलाई, प्रांतीय पदाधिकारी अशोक मोदी कोरबा,सुरेश मंगल बिल्हा, युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सेक्सरिया दुर्ग, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अधिवक्ता बाबूलाल अग्रवाल रायगढ़, कन्हैया गोयल शक्ति, संतोष लोहिया राजनांदगांव, श्रीमती सुनीता लोहिया राजनांदगांव प्रमुख रूप से शामिल हुए

छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय इकाई अवार्ड से सम्मानित किया गया, तथा अवार्ड से सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यों की प्रशंसा की एवं पूरे देश भर में सर्वाधिक कार्य करने वाली प्रादेशिक इकाई बताया, बैठक के दौरान जी न्यूज़ के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मित्तल द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं उनके संगठन की सक्रियता पर भी उनकी खुले मंच से प्रशंसा की तथा डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदीप मित्तल विगत कई दशकों से निरंतर समाज का काम कर रहे हैं एवं देश भर में अग्रवाल समाज के बंधुओ को एकजुट कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का इन्होंने काम किया है जो की प्रशंसनीय है।

बैठक के प्रथम दिन हुई महत्वपूर्ण चर्चा में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के अंतर्गत राजनैतिक समिति, उद्योग एवं व्यापार समिति जिसमें हैदराबाद के आर एन गुप्ता को राष्ट्रीय संयोजक, प्रोफेशनल समिति जिसमें सीए,डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, रोजगार समिति, सामाजिक उत्पीड़न समिति, प्रशिक्षण शिविर समिति, इतिहास एवं साहित्यकार समिति, प्रशासनिक समिति, संस्कृतिक कार्यक्रम समिति, खेलकूद समिति,सदस्यता अभियान समिति जिसमें हैदराबाद के अजय अग्रवाल एवं सहसंयोजक रायगढ़ के अधिवक्ता बाबूलाल अग्रवाल को बनाया गया, कुरीति उन्मूलन समिति, कंप्यूटर प्रशिक्षण समिति जिसमें बेंगलुरु के ओपी पोद्दार को बनाया गया, कैरियर काउंसलिंग समिति,धार्मिक आयोजन एवं यात्रा समिति जिसमें कोटा राजस्थान की पूर्व विधायक श्रीमती पूनम गोयल को बनाया गया, चिकित्सा समिति जिसमें रायपुर के डॉक्टर अनिमेष चौधरी, पत्रिका संपादन समिति जिसमें नई दिल्ली के मेरी दिल्ली के डायरेक्टर राजेश गुप्ता को बनाया गया ।

दो दिवसीय कार्यक्रम का सफल संचालन राष्ट्रीय चेयरमेन श्री प्रदीप मित्तल जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भरूका एवं डॉक्टर गिरीश मित्तल के द्वारा किया गया। आयोजन समिति को इस शानदार आयोजन के लिए पूरे राष्ट्र से अनेक अनेक बधाइयां भी दी गई।

प्रमुख रूप से पारित प्रस्ताव – राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का अलंकरण समारोह आयोजित करने, शादी ब्याह में प्री वेडिंग बंद करने, राष्ट्रीय स्तर पर अग्रवाल समाज के न्यूनतम कार्यक्रम तय करने, अग्र महापुरुष विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी को राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार से भारत रत्न सम्मान देने हेतु पत्र लिखने, बुजुर्ग खुश होगा तो भारत महकेगा को सूत्र वाक्य के रूप में सामाजिक स्तर पर मान्यता प्रदान करने, समाज के शादी ब्याह में दिन के फेरे आयोजित करने जन जागरूकता अभियान चलाने, समाज में विवाह योग्य लड़के- लड़कियों की उम्र अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित किया जाए तथा इस प्रस्ताव पर प्रत्येक अभिभावकों से चर्चा कर अपने बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक विवाह कर देने के संबंध में आग्रह किया जाएगा, आदर्श समाज के निर्माण करने के लिए हमारे पारंपरिक रीति रिवाज को समाहित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक पुस्तिका प्रकाशित करने, अंग्रेजी दास्तां के प्रतीक राजा रानी के चित्र युक्त सिक्कों की जगह भगवान अग्रसेन जी के फोटो युक्त चांदी के सिक्कों का प्रचलन समाज के मांगलिक एवं अन्य कार्यक्रमों में करने स्तर पर समाज में होने वाले संबंध विच्छेदों के लिए,अग्र पंचायत समिति का गठन करने ,अग्र सेना का गठन करने पर चर्चा, उच्च शिक्षा चाहने वाले यूपीएससी के बच्चों के लिए दिल्ली एवं अन्य स्थानों पर निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने, ,सहित विभिन्न प्रस्तावो पर चर्चा कर निर्णय लिये गए, तथा वृंदावन की बैठक में पहली बार राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल के प्रयासों से देश भर की विभिन्न प्रांतीय इकाइयों से समाज हित में प्रस्ताव मंगाए गए, जिसके प्रतिफल स्वरूप लगभग 100 प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त हुए जिसमें प्रस्ताव 50 प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर निर्णय लिए गए

खास खबर

गंभीर बिमारियां से बचाव व रोकथाम के लिए कार्यशाला

भिलाई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत डेंगू ,मलेरिया, फाइलेरिया, कुष्ठ , टी.बी.रोग तथा जलजनित बिमारियों के रोकथाम के लिए समन्वय एवं आने वाली बाधा को दूर करने में पार्षद व जनप्रतिनिधियों की भूमिका विषय पर निगम के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला मे महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी ,केशव चौबे, लाल चंद वर्मा, नेहा साहू, मीरा बंजारे, जोन अध्यक्ष भुपेन्द्र यादव, राजेश चौधरी, पार्षद सुरेश वर्मा,के.जगदीश कुमार,ईश्वरी नेताम,शकुंतला साहू,सरिता देवी, नोमिन साहू, गिरिजा बंछोर, डी.सुजाता, साथ ही डां. पियोम ,तुषार वर्मा, लक्की दुबे, मितानिन आदि उपस्थित थे।

मर्चेंट मिल ने टीएमटी बार उत्पादन का बनाया या कीर्तिमान

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की मर्चेंट मिल ने 9 मार्च 2024 को 550 डी ग्रेड में 3036 टन टीएमटी 32 बार्स की रोलिंग कर, 23 सितंबर 2023 को स्थापित पिछले सर्वश्रेष्ठ 2955 टन को पार कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। मिल ने वित्तवर्ष 2022-23 के अप्रैल से फरवरी अवधि के दौरान दर्ज 5.43 लाख टन उत्पादन को पार करते हुए वर्तमान वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.07 लाख टन टीएमटी बार्स और लाइट स्ट्रक्चरल का उत्पादन कर पिछले वर्ष की तुलना में 11.9 प्रतिषत की वृद्धि दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि मर्चेंट मिल उच्च जंगरोधी एचसीआरएम ग्रेड में टीएमटी बार, 550 डी ग्रेड में टीएमटी बार, टीएमटी (एसईक्यूआर-550 डी) और टीएमटी (एफई-500डी) सहित कई स्पेषल वैल्यू एडेड स्टील ग्रेड की रोलिंग करती है। मिल, एंगल और चैनल्स सहित लाइट स्ट्रक्चरल श्रेणी उत्पादों में कई स्पेषल स्टील ग्रेड्स की रोलिंग भी करती है।

बीएसपी के वित्त और लेखा विभाग ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के वित्त और लेखा विभाग द्वारा 9 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम में बहुत सारी नई चीजों के सीखने, साझा करने और मजेदार गतिविधियों से भरपूर था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) डॉ अशोक कुमार पंडा और विशेष अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक (एफएंड ए) श्री डी एन करन उपस्थित थे। डॉ अशोक कुमार पंडा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं अपने विकास और जीवन के प्रति बहुत केंद्रित हैं और यह अच्छी बात है कि वित्त विभाग में अब महिलाओं का अनुपात काफी अच्छा है। विभाग में महिलाएं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और आप महिलाओं को काम देंगे तो काम होगा ही और वह भी पूरी लगन के साथ। डी एन करण ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजकल महिलाएं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफमें बहुत अच्छा कर रही हैं। वे घर पर भी अच्छे से काम कर रहीं हैं और ऑफिस में भी अपना परचम लहरा रहीं हैं। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम 'इंस्पायर इंक्लूजन' पर उप प्रबंधक (वित्त और लेखा)संजोला द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर वर्क लाइफबैलेंस पर सुश्री बिंदु प्रकाश की वार्ता, नीना प्रदीप और चंद्रलता चंद्राकर द्वारा कविता का पाठ भी किया गया। इस खेल का संचालन जुलेखा ने किया। जबकि समग्र कार्यक्रम एवं प्रश्नोत्तरी का संचालन एम टी टी (एचआरडी) पूजा सिंह द्वारा किया गया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने श्रीरामलला के दर्शन कराने अयोध्या जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

जय श्रीराम के जयकारों से राममय हुआ बिलासपुर रेलवे स्टेशन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या जा रही विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी इस दौरान मौजूद थे। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं का विशेष जत्था जय श्रीराम का नारा लगाते हुए अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। वे अयोध्या में श्रीरामलला के साथ ही काशी में बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे।

राज्य सरकार के रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेशवासियों को नि:शुल्क अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन की रवानगी के समय विधायक सर्वश्री अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला, बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान, भूपेन्द्र सवन्नी और रामदेव कुमावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि यह क्षण हमारे लिए गौरवशाली है कि बिलासपुर संभाग के लोग रामलला दर्शन के लिए जा रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोदी जी की एक और गारंटी पूरी की है। इन श्रद्धालुओं का उल्लास और उमंग दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में रामलला के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा और आस्था है। 850 श्रद्धालुओं के इस जत्थे के लिए सरकार ने पूरा प्रबंध किया है। उनके आने-जाने, रूकने, खाने-पीने और मंदिर दर्शन की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जैसे ही अयोध्या के लिए जाने वाली विशेष ट्रेन "भारत गौरव ट्रेन" को हरी झंडी दिखाई गई, स्टेशन का पूरा वातावरण जय श्रीराम के जयकारे से गूंज उठा। यह 12 कोच वाली ट्रेन 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही है। वे काशी जाकर बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे।

श्रद्धालुओं ने कहा अयोध्या धाम का दर्शन करना सौभाग्य की बात

अयोध्या जा रही ट्रेन में सवार सावित्री गुप्ता ने कहा कि उसे बहुत खुशी है कि वह श्रीरामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम जैसे लोगों के लिए यह असंभव था। लेकिन मुख्यमंत्री की पहल पर आज हमें अयोध्या में श्रीरामलला का दर्शन संभव हो रहा है। बिलासपुर के सरजू बगीचा निवासी दीपक मिश्रा ने कहा कि बुजुर्गों को सरकार तीर्थ यात्रा का पुण्य दे रही है। सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। परसदा निवासी गणेश राम रजक ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है। लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते यह संभव नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा से धन्य हो रहे हैं जो हमें रामलला के दर्शन का अवसर मिल रहा है।

खाद्य मंत्री ने संबलपुर में नवीन पुलिस थाना चौकी का किया शुभारंभ

रायपुर। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने प्रवास के दौरान बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम संबलपुर में नवीन पुलिस थाना चौकी का शुभारंभ किया। और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। और बेहतर पुलिसिंग से क्षेत्र में हो रहे अपराध में लगेगी लगाम। इस अवसर पर दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर रणबीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण साहू सहित पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहे।

कारगिल में जौहर दिखाने वाले जाबांज सुबेदार संतोष 30 वर्ष की सेवा के बाद लौटे भिलाई, विधायक रिकेश ने किया अभिनंदन

भिलाई। भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी पद से रिटायर्ड 30 वर्षों की सेवा देकर भिलाई का बेटा संतोष माली आज 12 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस से पावर हाउस रेलवे स्टेशन पहुंचे। पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत कर गाजे बाजे के साथ किया गया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने उनकी अगुवानी कर नाम, नमक और निशान के प्रति वफादारी, शौर्य, साहस, त्याग, बलिदान के सबक को अपना कर सेवानिवृत्त हुए जाबांज सुबेदार संतोष को बधाई दी।

आपको बता दें कि 17 जून 1976 भिलाई-3 बजरंग पारा में माली परिवार में जन्में संतोष ने जनता स्कूल भिलाई-3 से 11वीं तक शिक्षा प्राप्त कर स्कूल के दौरान खेलों में एवं भारतीय स्काउट में भी जनता स्कूल का नाम रौशन किया था। 24 फरवरी 1994 को साढ़े 16 वर्ष की उम्र

में भारतीय सेना में चयनित हुए। इनका प्रशिक्षण एक सैनिक के रूप में एओसी सिकंदराबाद में हुआ। सेना में बेस्ट ग्रुप सोल्जर और बेस्ट फायरर का मेडल प्राप्त किया गया! कमांडेए एओसी सेंटर द्वारा सम्मानित ट्रेनिंग के बाद 1995 में पहली पोस्टिंग अंबाला छावनी में हुई।

इसी दौरान 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय में एक सिपाही की बेहतर भूमिका अदा करने के बाद संतोष की दूसरी पोस्टिंग 1998 में श्रीनगर छावनी में हुई। खेलों में हमेशा रुचि रखते हुए 14 किमी रन में लगातार 4 साल प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल जीता। वो 2019 में भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड अफसर बने। अपनी 30 साल सेवा के दौरान संतोष ने ऑटोमोबाइल एवं इंदिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी और इन्वेंटरी मैनेजमेंट डिप्लोमा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंस्टिट्यूट ऑफ कोआपरेटिव मैनेजमेंट हैदराबाद से स्माल बिजनेस रूरल एंटर प्रेन्योरशिप में उन्हें प्रथम स्थान मिला। आज सुबेदार संतोष कुमार माली ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को भारतीय सेना में भर्ती होकर, अग्नीवीर में भर्ती होकर अपने देश का, माता पिता का नाम रौशन करने का संदेश देते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सब अग्निवीर में शामिल होकर सोल्जर बनें, सभी सोल्जर हों तो कोई भी दुश्मन देश हमारे देश पर आँख उठाने कि हिम्मत नहीं कर सकता।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की बैठक लेकर की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, कहा-

समस्याओं की गठरी न बांधे, त्वरित निराकरण करें

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाकर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी ठेकेदारों के भरोसे न रहकर स्वयं फील्ड का दौरा करें और कार्यों की प्रगति देखें। उन्होंने शासकीय काम-काज में आने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। विधायक धरमजीत सिंह और श्री

सुशांत शुक्ला तथा बिलासपुर के महापौररामशरण यादव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों का परिचय लेने के बाद विभागवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आसन्न गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल एवं मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि कार्यालय से ज्यादा फील्ड में समय बिताएं। जानकारी के लिए केवल ठेकेदारों पर आश्रित न रहें। उन्होंने जल संसाधन विभाग में एक दशक से ज्यादा समय तक लंबित कामों पर नाराजगी जाहिर की। श्री साव ने जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में इनका समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्याएं बीमारी की तरह होती हैं। समय पर समाधान नहीं किए जाने पर नासूर बन जाती हैं। पीएचई विभाग द्वारा सड़क खोदने के बाद इसे खुला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने इस तरह के कार्यों पर रोष जताते हुए काम हो जाने के बाद तुरंत सड़क ठीक करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि काम-काज का तौर-तरीका अब बदल गया है। बदले माहौल के अनुरूप अधिकारी अपने आप को ढाल लें। पुराना ढर्रा नहीं चलेगा।

उन्होंने एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने को कहा। नाइट लैण्डिंग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर सड़कों की मरम्मत करने एवं गड्ढे पाटने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग में किसानों के पम्प ऊर्जीकरण के लिए लम्बित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा।

छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधी परीक्षा समाप्त, परीक्षा पूर्व तैयारी से बच्चों को हुआ लाभ

दुर्ग। दुर्ग जिले में 135 परीक्षा केन्द्रों में 30980 10वीं एवं 12वीं विद्यार्थियों का तनाव समाप्त हो गया है। क्योकि 10वीं की 3 पेपर व 12वीं के 04 पेपर समाप्त हो चुके है। इस सत्र में विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। क्योकि जिला शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न बैंक के माध्यम से प्रतिदिन प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखने की तैयारी जनवरी और फरवरी माह में प्राचार्यो और शिक्षकों के माध्यम से प्रतिदिन करायी गयी। जिसमें हमने उत्तर लिखने का भय व परीक्षा के भय समाप्त सा हो गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाई/हायर सेकेण्डरी की परीक्षा 01 मार्च 2024 से 23 मार्च 2024 तक आयोजित है। जिसमें 01 मार्च 2024 से 11 मार्च 2024 तक कलेक्टर द्वारा एवं जिला शिक्षा विभाग नियुक्त उड़न दस्ता दलों द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा पूर्व में गठित समिति द्वारा 157, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा 53, सहायक संचालक द्वारा 54, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा 36, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाटन द्वारा 35 एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धमधा द्वारा 18 परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है।

निगम का विशेष सभा 15 को: रिसाली के सभी मुक्तिधाम में केवल 100 रूपए में शव दाह के लिए लकड़ी

रिसाली। महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता वाली परिषद ने संवेदनशील मामले में बड़ा निर्णय लिया है। रिसाली मुक्तिधाम की तर्ज पर पुरैना, डुण्डेरा, जोरातराई, नेवई क्षेत्र में भी अंतिम संस्कार के लिए नि:शुल्क लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त निर्णय एमआईसी बैठक में लिया गया। खास बात यह है कि रिसाली निगम क्षेत्र के सभी मुक्तिधाम में एकरूपता और शोक संतप्त परिवारों को नि:शुल्क लकड़ी उपलब्ध कराने दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने पत्र लिखा था। महापौर ने संवेदना भरे पत्र को एमआईसी में प्रमुखता से रखवाया था।

महापौर शशि सिन्हा ने कहा है कि अंतिम संस्कार के लिए निगम क्षेत्र के सभी

मुक्तिधाम में नि:शुल्क लकड़ी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लकड़ी के साथ छेना या कंडा भी उपलब्ध कराया जाए। कंडा बनाने के लिए महिला समूहों को जोड़ा जाए। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होगी। उल्लेखनीय है कि रिसाली निगम में अंतिम संस्कार किए जाने पर केवल 100 रूपए लेकर लकड़ी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं अब यह व्यवस्था नेवई, डुण्डेरा एवं जोरातराई मुक्तिधाम में भी लागू होगी। महापौर परिषद की बैठक में चन्द्रभान सिंह ठाकुर, गोविन्द चतुर्वेदी, अनुप डे, सनीर साहू, सोनिया देवांगन, परमेश्वर कुमार, निगम सचिव रोहित साहू, कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे समेत विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

जर्जर भवन को गिराया जाए

नवीन शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के बीच आ रहे जर्जर पंप हाऊस को तोड़ने महापौर परिषद ने निर्णय लिया। वहीं वार्ड क्रमांक 37 जोरातराई गांधी चैक पर बने फौव्वारा को हटाने का भी निर्णय लिया। फौव्वारा पूर्ण रूप से खराब व जर्जर हो चुका है।

जमीन तलाशे अधिकारी

निगम क्षेत्र में स्वीकृत शासकीय अस्पताल, कॉलेज, मंडी के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की है। महापौर परिषद ने निर्देश दिए कि रिक्त भूमि नहीं होने की वजह से राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अधिकारी बीएसपी से चर्चा कर जमीन आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाए।

15 को होगा बजट प्रस्तुत

महापौर शशि सिन्हा 15 मार्च को तीसरा बजट सदन में रखेगी। इसके लिए उन्होंने सामान्य सभा का विशेष सम्मिलन बुलवाया है। महापौर के पत्र पर सभापति केशव बंछोर ने मुहर लगा दी है। विशेष सामान्य सभा स्कूल भवन कार्यालय के सभागार में सुबह 10 बजे शुरू होगा।

कांग्रेस की टिकट पर कोई चुनाव लड़ने तैयार नही... नही मिल रहे प्रत्याशी :- राधेश्याम राठिया

लोकशक्ति। रायगढ़ लोकसभा भाजपा अधिकृत प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने कहा कांग्रेस को प्रत्याशी नही मिल रहे है। मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस हताश हो चुकी है। कांग्रेस के एक दावेदार द्वारा चुनाव लड़ने से भी इंकार किए जाने की बाते सामने आई है। राधेश्याम राठिया ने रायगढ़ की जनता को जागरूक बताते हुए कहा लंबे समय से क्षेत्र की जनता मोदी सरकार पर भरोसा जताती रही है और वे भी इस भरोसे को कायम रखेंगे। क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए प्रतिबद्ध राधेश्याम राठिया ने स्मरण दिलाते हुए कहा पृथक छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाने का सपना स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने पूरा किया। आजादी के सात दशकों तक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद जी काम कांग्रेस ने नही किया वो अटल बिहारी जी की सरकार ने कर दिखाया। काम करने के लिए हौसलों और इच्छा शक्ति की आवश्यकता बताते हुए राधेश्याम राठिया ने कहा जनता के वोटो की शक्ति से मोदी सरकार ने तीन तलाक जैसी कुरूती को समाप्त किया धारा 370 को खत्म किया और राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

संपादकीय

कांग्रेस भगवान राम का विरोध क्यों कर रही

ए राजा और उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को बीमारी बताते हुए उसे खत्म करने का संकल्प जताया था।इस बीच राहुल गांधी का भी एक बयान चर्चा में आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनको तो खुद प्रधानमंत्री बनना है लेकिन वे चाहते हैं कि बाकी लोगों के बच्चे जय श्रीराम बोलते हुए भूख से मर जाएं। वे सीधे भूख से मर जाने की बात भी कर सकते थे या जैसा पहले कहा था कि मोदी चाहते हैं कि देश के बच्चों को मोबाइल की लत लग जाए और वे कोई काम नहीं करें, वैसा भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने जय श्रीराम नारे का जिक्र किया। गौरतलब है कि गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया और अन्य लोगों ने इसी बात को मुद्दा बनाया कि कांग्रेस भगवान राम का विरोध कर रही है। सबको पता है कि यह बहुत संवेदनशील मामला है फिर भी कैजुअल तरीके से इसे लेकर बयान दिए जा रहे हैं।उधर लालू प्रसाद ने पटना की जन विश्वास रैली में प्रधानमंत्री मोदी के संतान नहीं होने का मुद्दा उठाया और साथ ही यह भी कहा कि वे हिंदू नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल नहीं मुड़वाए। सोचें, डॉक्टर लोहिया के चेलों को इस पोंगापंथी विचार का प्रचार करना है कि हिंदू होने के लिए बाल मुड़वाना जरूरी है। लालू प्रसाद को हिंदू धर्म की विविधता और विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक के मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में अपनाई जाने वाली धार्मिक पद्धतियों की जानकारी ही नहीं है। क्या विपक्षी नेता इस तरह के बयानों से भाजपा के मुकाबले कुछ खास किस्म का ध्रुवीकरण होने की उम्मीद कर रहे हैं?

भारतीय संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों एवं धरातलीय विकास की वैश्लेषिक पारदर्शिता

भारतीय संदर्भ में महिलाओं के विकास स्वतंत्रता एवं सशक्तिकरण की अलग-अलग तस्वीर पेश की जाती रही हैद्य शासकीय आंकड़ों के हिसाब से उच्च प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल 14त्न लगभग भूमिका या भागीदारी है ।निजी क्षेत्रों में जो व्यापक स्वतंत्रता एवं उदारीकरण है, वहां भी महिलाओं की उच्च पदों पर पदस्थापना 20त्न से अधिक नहीं हैद्य सामाजिक संगठन बड़े जोर शोर से महिला स्वतंत्रता एवं सशक्तिकरण के बड़े-बड़े दावे पेश करते हैं, कुल जनसंख्या का 45त्न महिलाओं का होने के बाद भी भारत में महिला पुरुषों से कम दक्ष एवं कमजोर मानी जाती रही हैद्य वास्तविक स्थिति दर्शाये आंकड़ों के विपरीत ही हैं। भूमंडलीकरण शिक्षा में वृद्धि मानव अधिकारों की वृद्धि एवं सजगता से महिला सशक्तिकरण के आंदोलनों को काफी बल प्राप्त हुआ है। शनी सिगनापुर, हाजी अली दरगाह एवं अन्य स्थानों पर महिलाओं के प्रवेश के लिए सशक्त आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। आज से 20 वर्ष पूर्ण इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थीद्य वर्तमान ओलंपिक 2021 में पूर्वोत्तर राज्य की मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक दिलाकर अपनी क्षमता शक्ति एवं ऊर्जा को प्रदर्शित कर यह बता दिया है कि नारी विशेषकर भारत की पुरुषों से कहीं आगे हैं और प्रिया मलिक ने हंगरी में स्वर्ण पदक लाकर बात को प्रमाणित भी कर दिया हैद्य भारत की महिलाएं, साक्षी मलिक ओलंपिक में कांस्य पदक, पी,वी संधू रजत पदक, दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में पहली भारतीय महिला द्वारा स्वर्ण प्राप्त,साइना नेहवाल सानिया मिर्जा ने काफी हद तक महिलाओं के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है। इसी प्रकार निजी क्षेत्रों में चंदा कोचर,इंदिरा नूई, अरुंधति भट्टाचार्य ने आर्थिक जगत की नई ऊंचाइयों को छुआ है। अंतरिक्ष में कल्पना चावला सुनीता विलियम्स ने महिलाओं को बड़ी प्रेरणा दी है, राजनैतिक क्षेत्र में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 महिला मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह किरण बेदी ने पुलिस प्रशासन में एक बड़ी पताका हासिल कर महिला होने पर गर्व करने के लिए लोगों को मजबूर किया हैद्य

भारत के संदर्भ में यह माना जाए कि जीवन काल में ही महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कम स्वतंत्रता प्राप्त है। बचपन के पश्चात जब महिला विद्यालय, विवाह की ओर अग्रसर होती है, तो उसके पहनावे की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता हैद्य महिलाओं के वस्त्रों के साथ उसके चरित्र की व्याख्या कर दी जाती है। जबकि इस भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के युग में जहां संस्कृति के आदान-प्रदान का बड़ा महत्व है, और महिलाएं आधुनिकरण के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उनका परिवार समाज उन्हें इन सब कार्यों से दूर रख बाधित कर विकास की एक धारा को नियंत्रित कर देता है ।और इस तरह उनके मानसिक स्वतंत्रता को रोक कर उन्हें मानसिक दासता का पात्र बना देता है।घरों में समाज में सदैव लड़कों को घर का उत्तराधिकारी मानकर उन्हें प्रत्येक कार्य में वरीयता प्रदान की जाती है,एवं घर की लड़कियों को कमतर आंक कर केवल घर के कामों में ही व्यस्त रखा जाता है।, यह छोटे या बड़े अंतर ही महिलाओं को मानसिक रूप से गुलामी के लिए मजबूर कर वैचारिक हथकड़ियां पहनाते हैं।

हमें विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी उनकी भूमिका योगदान एवं स्थिति को एकदम स्पष्ट करना आवश्यक है। बहुत महिलाओं की भूमिका का परीक्षण अत्यंत छोटे स्तर पर करना आवश्यक है। महिलाओं को बचपन से ही मानसिक तथा शारीरिक स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार की प्रेरणा दी जानी चाहिए।- संजीव ठाकुर

श्रीनगर में मोदी ने बताई सच्चाई!

श्रुति व्यास

संविधान के अनुच्छेद 370 की जद से जम्मू-कश्मीर को बाहर किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 मार्च को पहली बार कश्मीर घाटी पहुंचे। प्रधानमंत्री बतौर दूसरी पारी में यह उनकी पहली कश्मीर यात्रा थी। दूसरी बार सत्ता में आने के तुरंत बाद उनकी सरकार ने उस संवैधानिक प्रावधान को जम्मू-कश्मीर से हटाने की कवायद शुरू कर दी थी, जो राज्य को पीछे धकेल रहा था, उसकी प्रगति की राह में रोड़ा था ।गत 7 मार्च को पहली बार उन्होंने कश्मीर से हमें यह याद दिलाया कि अनुच्छेद 370 कश्मीर का गला घोंट रहा था। अगर राजनैतिक नज़रिए से देखा जाए तो यह याद दिलाने की लिए कश्मीर से बेहतर जगह कौन-सी हो सकती थी? यह एक महत्वपूर्ण यात्रा थी जिसमें मोदी ने कई सन्देश दिए, जुमलेबाजी भी की और अपने राजनैतिक कौशल का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि जो नैरेटिव वे बुनते हैं, उससे जऱा भी इधर-उधर नहीं होते ।कश्मीर को हमेशा से दुहा और बेचा जाता रहा है

ङ्क राजनैतिक सन्दर्भ में, सामाजिक सन्दर्भ में, भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से, धर्म और पहचान की नाम पर और अपनी-अपनी आपबीती के ज़रिये। वहां के रहवासियों ङ्क मुसलमानों और पंडितों ङ्क दोनों ने उसे बेचा, अपने-अपने नैरेटिव के ज़रिये।और दोनों के नैरेटिव में दर्द है और दोनों के नैरेटिव दिल दहलाने वाले हैं। फिर कलाकारों, फोटोग्राफरों और फिल्म निर्माताओं ने कश्मीर को बेचा। उसकी कुदरती खूबसूरती और खूनखराबा, वहां की हसीन वादियाँ और हवा में तैरता डर, शांत माहौल को चीरती आहें और गुस्सा ङ्क इन सबको अगणित बार दुहा और बेचा गया।अनुच्छेद 370 और 35ए के विशेष प्रावधानों से कश्मीरियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिला ङ्क न आज़ादी, न गौरव, न स्वायत्ता और ना शांति और ना ही किसी लाभ की गारंटी। कश्मीर को बेच कर सबने फायदा कमाया और सबसे बड़े लाभार्थी थे राजनेता। जब राजनीति बांटने लगती है, ज़हर फैलाने लगती है तब सबसे ज्यादा कष्ट भोगते हैं आम लोग।कश्मीर और उसके लोगों ङ्क विशेषकर उन मुसलमानों, हिन्दुओं, सिक्खों और ईसाईयों ने जो अपने घर छोड़ कर नहीं गए और जो उथलपुथल और नीरवता दोनों को झेलते हुए वहीं रहे आए ङ्क ने बहुत कुछ भोगा है और बहुत लम्बे समय तक भोगा है। शांति के दिन छोटे और कम रहे और गड़बडियों और बेचैनी के रातें लम्बी और ज्यादा रहीं। बल्कि बेचैनी, असंतोष और गुस्सा कश्मीर की पहचान बन गए।सन 2019 के चुनाव में भी कश्मीर को एक राजनैतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। कश्मीर पर लिखा गया, कश्मीर पर बोला गया, कश्मीर पर फिल्में बनीं। इन सबमें जो नैरेटिव बनाए गए उनमें भी और राजनैतिक प्रचार में भी, हिंसा छाई रही। और हिंसा ही कश्मीर का नैरेटिव बन गई। कश्मीर विलाप और विषाद की घाटी बन गई।मगर 5 अगस्त, 2019 को इस सब पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। नतीजा यह कि कईयों के लिए नरेन्द्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो निर्णय लेना जानते है और जो निर्णय लेते है। वे एक तानाशाह नेता लगते हैं, उनके व्यवहार में दादागिरी का पुट है, नीतियों के निर्माण और उन पर अमल का उनका तरीका गैर-प्रजातान्त्रिक प्रतीत होता है और आने वाली पीढियों को कदाचित उनकी विरासत उतनी शानदार नहीं लगेगी जितनी हमें अभी लगती है।लेकिन कश्मीर के मामले में उन्होंने जो किया उसके लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे और 370 एक ऐसा अंक होगा जो भुलाया नहीं जा सकेगा। कश्मीर की बेडियाँ काट दी गईं हैं। दर्द और दहशत के नैरेटिव के सौदागरों को नये नैरेटिव ढूँढने पड़ रहे हैं। इनमें अब प्रजातंत्र के अभाव का मसला जुड़ गया है।सन 2019 के बाद कश्मीर की मोदी की इस पहली यात्रा के राजनैतिक निहितार्थ भी हैं। आम चुनाव के पहले मोदी ने बख्शी स्टेडियम के मंच से अपना नैरेटिव देश के सामने पेश किया। वसंत की उस सुबह हवा में ठंडक तो थी मगर आसमान साफ़ था और धूप भली लग रही थी। प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा की लिए 370 केवल एक नंबर नहीं है बल्कि एक गंभीर सोच का प्रतीक है।वे उस नैरेटिव से जऱा भी इधर-उधर नहीं हुए, जो नैरेटिव उन्हें ताकत देता है। चुनाव की पूर्वसंध्या पर कश्मीर के दिल से उन्होंने दरअसल कश्मीर को नहीं बल्कि भारत को संबोधित किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में उन्होंने कश्मीर के बारे में एक ऐतिहसिक और साहसिक कदम उठाया था। उन्होंने भारत को उन दीवारों की याद दिलाई जो कश्मीर और शेष भारत के बीच तामीर कर दी गईं थीं। उन्होंने कश्मीर के पुराने राजनीतिज्ञों की गन्दी करतूतों की याद दिलाई जिन्होंने कश्मीर को इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत से जुदा कर दिया था।उन्होंने भारत को याद दिलाया कि उसी वेदना में से कमल खिला है। उन्होंने भारत को याद दिलाया कि कश्मीर को अब एक नई राजनीति आकार दे रही है जो कश्मीर के लोगों को देश की अन्य हिस्सों के लोगों से जोड़ रही है। उन्होंने भारत को याद दिलाया कि विकसित भारत' के उनके मिशन का कश्मीर एक आवश्यक हिस्सा है और वह उसमें एक आवश्यक भूमिका निभाएगा।इसके पहले कि मैं नरेन्द्र मोदी की नई राजनीति' के पीछे की राजनीति की बात करूं और उनके नैरेटिव पर आऊं, थोड़ी चर्चा नए जम्मू-कश्मीर की। हो सकता है कि आप हर चीज़ में कुछ न कुछ नुक्स ढूँढने में माहिर हों, हो सकता है कि आप मोदी और उनके सरकार के अंध विरोधी हों, मगर फिर भी आप कश्मीर में आये बदलावों को नजरअंदाज़ नहीं कर सकते। निसंदेह कुछ कश्मीरी एक ही सोच से चिपके रहना चाहते हैं।वहां के कुछ बुद्धिजीवियों की लिए कश्मीर की पहचान' (जिसकी परिभाषा बहुत साफ़नहीं है) सबसे अहम, सबसे ऊपर है। फिर चाहे इसका मतलब सतत लूट, पहचान का राजनीतिकरण, उसे अन्य पहचानों से जुदा करना, लोगों को कट्टर बनाना, उनका दमन करना और कश्मीर की भूमि और उसकी पहचान को अतीत में धकेलना ही क्यों न हो।इसलिए यह ज़रूरी है कि हम द्वेष के लेंस लगे चश्मे उतार कर जम्मू-कश्मीर और विशेषकर घाटी में हुई प्रगति को देखें। कश्मीर को बहुत समय बाद विकास का स्वाद चखने को मिल रहा है, वह प्रगति और शांति, ग्लैमर और चमक-दमक का मज़ा ले रहा है। कश्मीर का मतलब अब हिंसा नहीं है। वहां शांति है। अल्पसंख्यकों की हत्याएं और सेना पर हमले कब-जब इस शांति को भंग करते हैं मगर तुलनात्मक रूप से शांति तो है ही।लोगों का मूड बदल रहा है। वे अब खुल कर बात करते हैं। वे अपने नए भविष्य, जो सुनहरा है, को गले लगाने तैयार हैं। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके गुलज़ार हैं। निराशा भी उतनी निराशाजनक नहीं लगती। राजनीति में एक नयापन है, एक नया परिप्रेक्ष्य है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पूरी निष्ठा और समर्पण से इस कोशिश में लगे हैं कि प्रगति और उन्नति के साथ-साथ, राजनीति को भी जगह मिले, मगर एक नए कैनवास पर।नए कश्मीर में एक नई तरह की राजनीति अंगड़ाई ले रही है। अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों की राजनीति उतनी ही दयनीय अवस्था को प्राप्त हो चुकी है जितनी कि राहुल गाँधी और तेजस्वी यादव की। निवेश आ रहा है, प्रगति हो रही है। सरकार की योजनाओं का फायदा पुलवामा के कश्मीरी को ही उतना ही मिल रहा है जितना बिहार के मांझी को।जैसा कि हम सब जानते हैं, आप कुछ करके ही मैदान जीत सकते हैं। केवल जुबानी जमाखर्च से कुछ होना-जाना नहीं है। कश्मीरियों को इस बात का अहसास है कि मोदी का जादू इस समय देश में सिर चढ़कर बोल रहा है और शक्ति और सत्ता मोदी के हाथों में केन्द्रित है। मोदी चुनाव के रणभूमि के भी विजयी योद्धा हैं। वे ही सब कुछ हैं।इसे कश्मीर की नियति कहें या और कुछ और मगर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पांच साल बाद भी वह चुनाव और सत्ता की खेल में महत्वपूर्ण मोहरा बना हुआ है। हालाँकि एक फर्क है। अब चर्चा हिंसा की नहीं होती। और यही मोदी की 7 मार्च की कश्मीर यात्रा को महत्वपूर्ण बनाता है।

यह निजी विचार है।

विशेषाधिकार में घूस लेने की छूट नहीं

अजीत द्विवेदी

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संसदीय पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफजस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बहुत दो टूक अंदाज में कहा है कि सदन के अंदर सांसदों को जो विशेषाधिकार मिले होते हैं उनमें रिश्वत लेने की छूट शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि विशेषाधिकार इसलिए दिया गया है ताकि सांसद किसी भी विषय पर खुल कर अपनी राय रख सकें ।बहस और विचार विमर्श में किसी तरह की बाधा नहीं आए, वह बेबाक हो, हर पहलू को समेटे हुए हो इसके लिए विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। इस टिप्पणी के साथ ही सर्वोच्च अदालत ने 26 साल पहले हुई एक गलती को सुधार दिया। अदालत का यह फैसला दूरगामी असर वाला साबित होगा और इससे संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही को भी स्वच्छ, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी ।अदालत के इस फैसले को समझने के लिए 1993 के जेएमएम रिश्वत कांड और 1998 में आए फैसले के साथ साथ 2012 के मुकदमे के बारे में जानने की जरुरत है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की अल्पमत सरकार पर आरोप लगे थे कि उसने 1993 में बहुमत साबित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्वत दी थी। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन सहित कई सांसद इसमें शामिल पाए गए थे। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) की व्याख्या करते हुए तीन-दो के बहुमत से फैसला सुनाया था कि संसद के अंदर सांसदों को हासिल विशेषाधिकार के तहत इस मामले में सांसदों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है।तब से यह स्थिति बनी हुई थी कि विशेषाधिकार के तहत रिश्वत लेना भी शामिल है। यानी कोई सांसद या विधायक अगर रिश्वत लेकर वोट करता है या सवाल पूछता है या बहस में हिस्सा लेता है तो उसके खिलाफसंसद या विधानसभा से बाहर मुकदमा नहीं चल सकता है।इतिहास कैसे त्रासदी के रूप में अपने को दोहराता है वह इस मामले में दिखा, जब 2012 के राज्यसभा चुनाव में शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के ऊपर रिश्वत लेकर निर्दलीय विधायक को वोट देने का आरोप लगा। जब उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ तो उन्होंने अपने ससुर के मामले में आए 1998 के फैसले का हवाला दिया और अपने लिए मुकदमे से छूट मांगी। इसी मामले में 2014 से नए सिरे से 1998 के फैसले की समीक्षा शुरू हुई। पहले तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की।फिर मामला पांच जजों की बेंच के पास गया और अंत में तय हुआ कि जब पहला फैसला पांच जजों की बेंच का है तो उससे बड़ी बेंच को इस पर विचार करना चाहिए ताकि स्पष्टता आ सके। चीफजस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सात जजों की बेंच ने दो दिन यह मामला सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत ने एक राय से पुराने फैसले को पलट दिया है और कहा है कि घूस लेना विशेषाधिकार नहीं है।अदालत ने कहा है कि घूस लेना अपने आप में एक आपराधिक मामला है। घूस लेने के बाद इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आपने जिस काम के लिए घूस लिया वह काम किया या नहीं। अगर किसी सांसद ने वोट देने के लिए रिश्वत ली है तो इससे मुकदमे की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिश्वत लेने के बाद उसने वोट दिया या नहीं या रिश्वत देने वाले के हिसाब से उसने संसद में बात की या नहीं। रिश्वत लेते ही अपराध का मामला बन जाता है।सो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्पष्ट और दो टूक है। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे संसद और राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही पहले से स्वच्छ होगी और ओवरऑल देश की राजनीति पर इसका सकारात्मक असर होगा। राजनेताओं की साख बेहतर करने में इस फैसले की अहम भूमिका हो सकती है।इस सकारात्मक पहलू के बावजूद जेएमएम की विधायक सीता सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील राजू रामचंद्रन ने जो दलीलें दीं और जो सवाल उठाए उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। उन्होंने सांसदों के विशेषाधिकार की मौजूदा व्याख्या को अधूरा और एकपक्षीय बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ रिश्वत लेकर वोट डालने के मामले पर विचार करने की बजाय सांसदों के आचरण, भाषण आदि पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए।असल में अदालत के सामने मौका था कि वह अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 की व्यापक व्याख्या करती और घूस के साथ साथ दूसरे पहलुओं को भी शामिल करती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत घूस लेने का अधिकार नहीं आता है। लेकिन क्या किसी सदन के अंदर किसी साथी सांसद को अपशब्द कहना या उसकी जाति या समुदाय को निशाना बना कर टिप्पणी करना संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में आएगा?गौरतलब है कि संसद की नई इमारत में आयोजित पहले सत्र में भाजपा के सांसद रमेश विधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे थे। उनके मामले में लोकसभा के स्पीकर को फैसला करने वाला अंतिम प्राधिकर माना गया। तभी सवाल है कि क्या उस मामले में भी आपराधिक मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए था?और अगर अभद्र या असंसदीय टिप्पणी करने पर कार्रवाई का अधिकार सदन के पीठासीन पदाधिकारी को है तो घूस के मामले में भी कार्रवाई का अधिकार उसी को क्यों नहीं होना चाहिए? ध्यान रहे पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में पहले लोकसभा ने कार्रवाई की थी। कोई 20 साल पहले 2005 में यह मामला आया था, जब लोकसभा के 10 और राज्यसभा के एक सांसद को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था।इसी तरह पैसे या उपहार लेकर लोकसभा में सवाल पूछने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचरण समिति की सिफारिश पर कार्रवाई हुई और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि आगे जब किसी सांसद या विधायक पर रिश्वत लेकर सदन के अंदर कोई काम करने का आरोप लगेगा तो क्या दोहरी कार्रवाई होगी या एक बार ही कार्रवाई होगी?क्या ऐसा हो सकता है कि आरोप लगते ही सदन का पीठासीन अधिकारी आचरण समिति को मामले भेजे और उसकी सिफारिश पर संबंधित सदस्य की सदस्यता खत्म कर दे और उसके बाद संसद से बाहर पुलिस या कोई दूसरी एजेंसी भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम करे? अगर ऐसा होगा तो यह प्राकृतिक न्याय के उलट होगा।कायदे से यह होना चाहिए कि आरोप लगने पर या तो संबंधित सदन कोई कार्रवाई करे या सदन से बाहर मुकदमा अदालत में ही चले। अगर दोहरी कार्रवाई होती है तो अन्याय की गुंजाइश रहेगी। ध्यान रहे महुआ मोइत्रा अगर जांच और अदालती कार्रवाई में बरी हो जाती हैं तो फिर उनकी खत्म की गई सदस्यता का क्या होगा? फैसले के इस पहलू पर स्पष्टता की जरुरत है।

यह निजी विचार है।

खास खबर

राज्य खेल अलंकरण समारोह-2024 : राज्य के खेल प्रतिभाओं का 14 को होगा सम्मान

रायपुर। राज्य के खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए 14 मार्च को राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्वीकृत 31 खेलो इण्डिया लघु केन्द्र, खेलो इंडिया सेन्टर, राज्य की सभी खेल अकादमियां एवं विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का 120 सेकेण्ड अवधि का वीडियो स्पॉट एच डी फॉरमेट में निर्माण कर 12 मार्च तक अनिवार्य रूप से संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण को उपलब्ध कराने कहा गया है। ज्ञात हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 31 जिलो में खेलो इण्डिया सेंटर्स की स्वीकृति दी गई है। इसमें राज्य के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जैसे आदिम जनजाति बाहुल्य जिले भी सम्मिलित है। इसी तरह 31 खेलो इंडिया सेंटर के साथ- साथ भारत सरकार द्वारा राज्य के बिलासपुर में भी तीन खेलो-हॉकी, एथलेटिक और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया एक्सिलेंस सेंटर की स्वीकृति दी गई है, जिसमें खिलाडियों के लिए आधुनिक खेल उपकरण तथा प्रशिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट आदि अन्य सुविधाएं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य के नारायणपुर जिले में मलखम्भ, बीजापुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद और बिलासपुर के शिवतराई में तीरंदाजी, गरियाबंद में व्हॉलीबॉल, सरगुजा, बलौदाबाजार, सुकमा, बलरामपुर, कोरबा, सूरजपुर, मुंगेली, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और सक्ति में फुटबॉल, जशपुर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और बस्तर में हॉकी, बालोद और रायपुर में वेटलिफ्टिंग, कबीरधाम, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बेमेतरा और दुर्ग के पाटन में कबड्डी, कांकेर में खो-खो, रायगढ़ और कोरिया में बैडमिंटन, धमतरी में कुश्ती, कोण्डागांव में आरचरी खेल का सेन्टर स्थापित है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विकास कार्यो में प्रगति लाने के दिए निर्देश

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एक दिवसीय प्रवास पर अपने प्रभार जिले बलरामपुर-रामानुजगंज पहुंची। उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। श्रीमती राजवाड़े ने शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को सक्रियता से पहुंचाने के साथ विकास कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल के कार्यो को प्राथमिकता से कर लोगों को बुनियादी सुविधाओं को सुलभ कराने के निर्देश भी दिये। राजवाड़े कहा कि आमजनता की समस्याओं को सुनने के साथ उनका निराकरण भी समय पर करना सुनिश्चित किया जाए। राजवाड़े ने कहा कि विकास के लिए आपसी समन्वय कर आगे बढ़ना है। सन् 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है, इसी के तहत् विकास कार्यों में प्रगति लाते हुए बलरामपुर जिले को भी विकसित बनाना है। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए अभियान चलाकर उन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में महतारी वंदन योजना, आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति, बाल संरक्षण की इकाई, सखी वन स्टॉफ सेन्टर की भी समीक्षा की गई। राजवाड़े ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए पेंशन योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने दिव्यांगजनों को अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण प्रदान करने तथा दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि निश्चित समयावधि देने को कहा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047' विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर कार्य शुरू

लोकशक्ति।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में ''अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047'' संबंधित विजन डॉक्यूमेंट बनाने की कार्ययोजना पर सभी विभागो के भारसाधक सचिवो के साथ बैठक ली। बैठक में मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा देश की आजादी के 100 वर्ष की पूर्णता पर 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु विजन साझा किया गया है, तथा अपेक्षा की गई है कि सभी राज्य विकसित भारत @2047 को साकार करने के लिए राज्य स्तर की नीतियों, कार्यक्रम व संसाधनों का प्रभावी क्रियान्वयन व उपयोग सुनिश्चित करें।

साथ ही राज्य की खूबियों को पहचान कर अपेक्षित प्रगति प्राप्ति हेतु प्रभावी रणनीति व कार्ययोजना का समावेश कर विजन तैयार करें। इसी परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट ''अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047'' जारी किये जाने हेतु संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में राज्य हेतु संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनीकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास, आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनो

का प्रभावी उपयोग, रिन्यूवेबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टैक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु - रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस संकलन हेतु तैयार किये गये ऑनलाईन डिजिटल पोर्टल 'नवोन्मेष पोर्टल' का लोकार्पण किया। इस पोर्टल का उद्देश्य बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रभावी व एक स्थान पर संकलन किया जाना है। जिसे अन्य जिले व विभाग संज्ञान में लेते हुये अपने कार्य क्षेत्रों में भी लागू करने हेतु प्रेरित होंगे तथा योजनाओं, गतिविधियों अंतर्गत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ. पी. चौधरी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु प्रस्तावित रणनीति पर विमर्श बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में की गई घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन आगामी राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट ''अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047'' जारी किये जाने हेतु संकल्पित है।

चौधरी ने कहा कि 'सर्वसमेकित विकास' एवं 'विकास की धारा में कोई पीछे न छूटे' की अवधारणा के साथ विकसित राष्ट्र व राज्य की परिकल्पना की गई है। राज्य के त्वरित विकास की अवधारणा में कुल 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ का चिन्हांकन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से (गरीब, यूवा, अन्नदाता एवं नारीशक्ति) हमारे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के केन्द्र बिन्दु होंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में लघु (5 वर्ष), मध्यम (10 वर्ष) एवं दीर्घकाल (25 वर्ष) हेतु सेक्टरवार रणनीतियो का समावेश होगा। रणनीति के साथ विजन डॉक्यूमेंट में- सेक्टरवार क्रियांवयन बिन्दुओं का भी समावेश होगा। विमर्श बैठक में अजय सिंह, उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य नीति आयोग द्वारा विभागो, जिला प्रशासन के अधिकारियों, इंडस्ट्री, सिविल सोसायटी, युवा व आम-जन से सुझाव प्राप्त कर सर्व समेकित विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाएगा। नीति आयोग, नई दिल्ली से भी आवश्यकतानुसार समन्वय किया जाएगा। उन्होंने अपेक्षा कि की सभी विभाग इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा सभी विभागो के सचिवो से राज्य नीति आयोग से पर्याप्त समन्वय, आवश्यकतानुसार डाटा फीड बैक प्रदाय हेतु परामर्श दिया गया, जिससे कि विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण में सभी विभागो की सहभागिता सुनिश्चित हो। बैठक में विजन डॉक्यूमेंट निर्धारण हेतु की जाने वाली चरणबद्ध कार्यवाही व उनकी समय-सीमा पर अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य, राज्य नीति आयोग व सभी विभागो के भारसाधक सचिव उपस्थित रहे।

बस्तर के विकास को गति के लिए बेहतर ढंग से कार्य करें: प्रभारी मंत्री अग्रवाल

रायपुर। शिक्षा मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विकसित बस्तर बनाना होगा। बस्तर के विकास के लिए सभी अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे बस्तर का तेजी से विकास हो सके। उन्होंने कहा कि बस्तर की शिल्पकलाओं की अलग पहचान है इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है। यहां के शिल्पकारों को चिन्हांकित कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री अग्रवाल आज जगदलपुर जिला मुख्यालय में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयान की समीक्षा कर रहे थे।

प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नगरनार एवं किलेपाल में नवीन कॉलेज खोलने के लिए जमीन चिन्हाकन की जानकारी ली और कॉलेज भवन, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए आवास सहित खेल मैदान इत्यादि के निर्माण हेतु 15-15 एकड़ भूमि चिन्हित कर आरक्षित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चित्रकोट जलप्रपात स्थल में विकास कार्यों को तेजी से करने पर जोर देते हुए लाईट एण्ड साउण्ड शो को प्रारंभ करवाने हेतु समुचित विद्युत आपूर्ति के लिए जल्द ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने का निर्देश दिए। उन्होंने कृषक उन्नति योजना के तहत जिले के किसानों के खातों में अंतर की राशि वितरण की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के द्वारा पात्र हितग्राही के खातों का आधार सिडिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने नियद नेल्लानार सहित केन्द्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्रीष्मकालीन पेयजल आपूर्ति हेतु पुख्ता व्यवस्था करने पर जोर दिया। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाओं को विशेष फोकस कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में मरम्मत योग्य स्कूलों के सुधार कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं। ऐसे स्कूल जहां एक एकड़ से अधिक जमीन हो उन जगहों पर वन विभाग के समन्वय से वृक्षारोपण करवाने की पहल की जाए। साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालन कर स्कूली बच्चों को आधुनिक पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इस हेतु बैंकों के सीएसआर मद का उपयोग किया जा सकता है।

खेती से अधिक लाभ के लिए नवीन अनुसंधानों और नवाचारो को अपनाएं किसान: मंत्री नेताम

रायपुर। कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि छतीसगढ़ सरकार राज्य में कृषि के विकास तथा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसान हितैषी सोच के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं और आगामी समय में सरकार द्वारा किसानों के हित में और कई नवीन योजनायें शुरू की जाएँगी। कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों से खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नवीन अनुसंधानों एवं नवाचारों को अपनाने का आह्वान किया।

नेताम यहाँ राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केंद्र अंबिकापुर में राज्य शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से आयोजित दो दिवसीय किसान मेला, नवाचार मेला तथा कृषि प्रदर्शनी ''अंकुरण'' का शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। समारोह में अंबिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल, लुन्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज तथा प्रतापपुर विधायक श्रीमती शंकुतला पोर्ते विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा गिरीश चंदेल ने की। इस अवसर पर सरगुजा क्षेत्र के प्रगतिशील एवं नवाचारी किसानों को सम्मानित भी किया गया।

किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री नेताम ने कहा कि सरगुजा की मिट्टी पानी और जलवायु सभी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। आज यहाँ लुन्ड्रा प्रतापपुर क्षेत्र सब्जियों की खेती के लिए विख्यात हो चुके है और यहाँ उत्पादित सब्जियां उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक जा रही है। इसके साथ ही सरगुजा अंचल में फलों मक्का गन्ना एवं मिलेट्स की खेती की व्यापक सम्भावनाए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन सभी की खेती को बढावा देने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने किसानों को अपनी फसलों की बेहतर मार्केटिंग के लिए कृषक उत्पादन संगठन बनाकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री नेताम ने किसानों से जैविक खेती करने तथा नदी तालाबों व संरक्षण के लिए प्रयास करने का अनुरोध कियाप् श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से प्रति क्विन्टल 3100 रूपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। राज्य सरकार द्वारा किसानों से कोदो, कुटकी, रागी आदि मिलेट्स की समर्थन मूल्य की खरीदी की जा रही है। श्री नेताम ने में कृषि के विकास इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे नवीन अनुसंधानों, तकनीकों तथा नवाचारों की प्रशंसा की। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की परम्परागत सुगन्धित एवं औषधीय किस्मों के संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे नवीन अनुसंधानों, नवीन प्रोद्योगिकी विकास तथा नवाचारो के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया की विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को उनके उत्पादों की सही कीमत दिलाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनो को सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा की कृषि विश्वविद्यालय नाबार्ड के सहयोग से सरगुजा क्षेत्र में कृषि आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने कि योजना है। डा गिरीश चंदेल ने बताया कि सरगुजा संभाग के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र माध्यम से किसानों को नवीन कृषि अनुसंधानों एवं तकनीको की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें लाभदायक फसलों की खेती एवं मार्केटिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

किसान मेले में कृषि महाविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित विभिन्न कृषि महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा अन्य इकाईयां द्वारा किसानों के लिए किये जा रहे नवीन अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इनके अलावा राज्य शासन के कृषि, एवं कृषि अभियांत्रिकी विभागों द्वारा संचालित किसान कल्याणकारी योजनाओं एवं गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया है। यहां नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कृषि उत्पादक समूहों तथा महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों एवं तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया है।

वित्त मंत्री ने किया रायगढ़ के कोयलंगा डायवर्सन सुधार कार्य का वर्चुअल भूमिपूजन

रायपुर। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने रायगढ़ विधान सभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोयलंगा में आज अपने राजधानी स्थित निवास कार्यालय से कोयलंगा डायवर्सन के सुधार कार्य का वर्चुअल भूमिपूजन किया।

2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में 275 हेक्टेयर की वृद्धि होगी और कोइलंगा के साथ भुइया पाली, बेहरा पाली के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इस परियोजना के वर्चुअल भूमिपूजन के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ के विधायक श्री ओपी चौधरी ने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की एवं आने वाले समय में केलो बांध और सपनाई बांध से भी जल्द ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का वायदा किया। गौरतलब है की केलो बांध के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

कबाड़ी गोदाम में छापा, जीएसटी विभाग ने ठोका 5.50 लाख का जुर्माना

बिलासपुर-रायपुर,। कबाड़ पर बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें पुलिस ने तांबा के कबाड़ से भरे 2 पिकअप को जब्त किया है. रायपुर से आ रही पिकअप इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा निवासी सुनील रेलवानी की थी. जिसकी जांच के बाद जीएसटी विभाग ने 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में छापामार कर 2 लाख 50 हजार रुपये का कबाड़ भी ज़ब्त किया है. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील रेलवानी तांबा से भरा हुआ कबाड़ 2 पिकअप के जरिए रायपुर की ओर से लेकर आ रहा है. जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर चकरभाठा थाना में दोनो पिकअप को रोककर चेक किया। दोनों पिकअप में अलग-अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था. जिसका जीएसटी बिल नहीं था. बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था।

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

//ई–प्रोक्योरमेंट //
//निविदा आमंत्रण सूचना//

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र –''ए'' में जल जीवन मिशन अंतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम/रेट्रोफिटिंग योजनांतर्गत जिला मोहला–मानपुर–अं.चौकी के विभिन्न विकासखंडो के विभिन्न ग्रामों में स्त्रोत निर्माण हेतु 150 मि.मी. व्यास के 120 मीटर गहरे नलकूप खनन के कार्य (दिये गये शेड्यूल अनुसार) की मुहरबंद निविदाए दिनांक 11.03.2024 से ऑन लाईन पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त कार्य के निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से दिनांक 18.03.2024 से डाउनलोड की जा सकती है तथा निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 01.04.2024 (शाम 5:30 बजे) तक है।

कं.	निविदा कंमाक	सिस्टम कंमाक	विकासखण्ड	नलकूप की संख्या	निविदा की लागत (रू.लाख में)
1	1	153964	मोहला	27	36.48
2	2	153965	मोहला	26	35.13
3	3	153970	मानपुर	33	44.59

G-08469/4

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ.ग.)

विकासखंड नवागढ़ के ग्राम पंचायत खोखरा में आजीविका ऋण मेला का हुआ आयोजन

आजीविका ऋण मेला में 749.54 लाख रुपए का विभागीय और स्व सहायता समूह का बैंक शाखाओं के माध्यम से किया गया ऋण स्वीकृत

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने मंगलवार को नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत खोखरा के मनका दाई मंदिर प्रांगण में लगाये गये आजीविका ऋण मेला में शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित हितग्राहियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आप दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सक्षम बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने कहा। साथ ही महिलाओं को योजना की जानकारी देते हुए आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। आजीविका ऋण मेला में 749.54 लाख का विभागीय और स्व सहायता समूह का बैंक शाखाओं के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया गया।

कलेक्टर ने आजीविका ऋण मेला में हितग्राहियों को चेक का वितरण किया। आजीविका ऋण मेला के माध्यम से स्व सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज में बढ़ोतरी, बैंक द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण वितरण क्षेत्र का विस्तार, शासकीय स्व-रोजगार ऋण योजनाओं के प्रति जागरूकता, मुद्रा योजना के क्षेत्र का विस्तार, स्वयं सिद्धा योजना के प्रति जागरूकता एवं विस्तार, नवीन बैंक खाते और आधार पंजीयन करने की सुविधा, ग्रामीणों की वित्तीय साक्षरता एवं सायवर फ्रॉड के रोकथाम के प्रति जागरूकता और अन्य बैंकिंग से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। इस अवसर पर लीड बैंक अधिकारी, जनपद सीईओ नवागढ़ सहित जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिकजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद से किया कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ

जिले के 1 लाख 22 हजार से अधिक किसानों के खातों में 587 करोड़ 58 लाख रूपए की राशि हुई हस्तांतरित

किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जताया आभार

जांजगीर-चांपा 12 मार्च 2024/ कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आज का दिन सदैव अविस्मरणीय रहेगा। आज छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24 लाख 72 हजार किसानों को योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रूपए की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से समारोह में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज वह शुभ दिन है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के बैंक खातों में 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का अंतरण किया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। जिसमें जिले के 1 लाख 22 हजार 836 किसानों के खाते में 587 करोड़ 58 लाख 26 हजार रूपए की राशि अंतरित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, नगर पालिका जांजगीर नैला उपाध्यक्ष श्री आशुतोष गोस्वामी, अपर कलेक्टर लवीना पांडेय सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान अपस्थित थे। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के लगभग 24 लाख से अधिक किसानों के खाते में 13320 करोड़ की राशि बटन दबा कर हस्तांतरित किये है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं को योजना के माध्यम से एक-एक करके पूरा कर रही है। जब किसान समृद्ध होता है, तब देश की उन्नति होती है। किसानों को समृद्ध बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। इस अवसर पर ग्राम सिवनी के किसान ईतवारी राम पटेल किसान ने कहा कि कृषक उन्नति योजना को लेकर हम बहुत खुश है हमे आज छत्तीसगढ़ सरकार का घोषणा के अनुरूप अंतर की राशि में प्राप्त हो गई है। इस योजना से छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुश हैं। किसान रामप्रकाश केशरवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपने वायदे को पूरा किया है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के साथ साथ समर्थन मूल्य के अंतर की राशि हमारे खाते में आया और इससे हम बहुत खुश हैं।

नि :शुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 01 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आधार कार्ड के आधार पर ऑनलाईन पोर्टल httpsÑ//eduportal.cg.nic.in/rte में आवेदन कर सकते है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आरटीई पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन में आवेदनकर्ता का आधार कार्ड के आधार पर निवास स्थल, वार्ड नं., मुहल्ला अंतर्गत संचालित होने वाले नर्सरी से कक्षा-पांचवी तक 1 कि.मी. तथा कक्षा छठवीं से आठवीं कक्षाओं तक 3 कि.मी. के भीतर आरटीई पोर्टल में पंजीकृत विद्यालय ही प्रदर्शित होगा। 31 मार्च 2024 की स्थिति में कक्षा नर्सरी के लिए 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य, कक्षा-केजी-1 के लिये 4 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य एवं कक्षा पहली के लिये 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होना आवश्यक है। आवेदन में आयु के अनुसार विद्यालय में संचालित आरटीई में प्रवेशित कक्षा अनुसार ही विद्यालय प्रदर्शित होगा। उक्त संस्था में नर्सरी एवं के.जी. -01 संचालित नहीं है तो उक्त विद्यालय पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होगा। आवेदन आरटीई पोर्टल से आवेदन प्रिंट नहीं होने पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर के आरटीई कक्ष क्रमांक-05 में आरटीई हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ से आप निःशुल्क आवेदन क्रमांक प्राप्त कर सकते है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऑनलाईन पोर्टल **httpsÑ//eduportal.cg.nic.in/rte** के माध्यम से जिले के 456 अशासकीय विद्यालयों हेतु 3864 सीट निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन पश्चात् 17 अप्रैल 2024 के भीतर सर्वे सूची एवं प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ सक्षम नोडल अधिकारी, संबंधित विद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

पं0 जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी

दावा आपत्ति 14 मार्च तक आमंत्रित

जांजगीर-चांपा पं0 जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कक्षा 6 वीं हेतु प्रवेश परीक्षा 10 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। जिसका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जांजगीर-चांपा ने बताया कि परीक्षा परिणाम के संबंध में 14 मार्च तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग में उपस्थित होकर दावा आपत्ति कर सकतें हैं। सूची का अवलोकन कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग जांजगीर-चांपा के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट **httpsÑ//janjgir-champa.gov.in/** पर अवलोकन कर सकते हैं।

10वीं की विज्ञान एवं 12वीं की लेखांकन विषय की परीक्षा संपन्न

जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आज आयोजित हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 10वीं की विज्ञान एवं 12वीं की लेखाकन विषय की परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हुई।

जिला शिक्षा अधिकारी कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय की परीक्षा में जिले के कुल पंजीकृत 16597 मे से 16097 विद्यार्थी शामिल हुए। जबकि 555 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। इस परीक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी की टीम द्वारा शा.उ.मा.वि नरियरा में 03 एवं शा.उ.मा.वि.तिलई में 01 कुल 4 नकल प्रकरण दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि विकासखण्ड अकलतरा में 2533, बलौदा विकासखण्ड में 2007, बम्हनीडीह विकासखण्ड में 2999, नवागढ़ विकासखण्ड में 5066, पामगढ़ विकासखण्ड में 3437 परीक्षार्थी उपस्थित थे। इसी प्रकार कक्षा 12वीं की लेखांकन विषय की परीक्षा में जिले कुल पंजीकृत 90 मे से 86 विद्यार्थी शामिल हुए। जबकि 4 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। इस परीक्षा में कोई भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। विकासखण्ड अकलतरा में 5, बलौदा विकासखण्ड में 12, बम्हनीडीह विकासखण्ड में 28, नवागढ़ विकासखण्ड में 31, पामगढ़ विकासखण्ड में 10 परीक्षार्थी उपस्थित थे।

कक्षा 10वीं की गणित विषय की ओपन परीक्षा संपन्न इसी प्रकार जिले में संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल ओपन परीक्षा 2023-24 हेतु आज कक्षा 10वीं की गणित विषय की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। गणित विषय की परीक्षा में कुल पंजीकृत 584 में से 512 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में 72 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहें। पूरक परीक्षा में नकल प्रकरण दर्ज नहीं किए गए हैं।

जिले के ऑगनबाड़ी केन्द्रों में किया गया स्वीप कार्यक्रम का आयोजन

जांजगीर-चांपा कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के निर्देशन में आज जिले के समस्त ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता (स्वीप) कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवविवाहित मतदाताओं का सम्मान किया गया एवं मताधिकार के प्रति जागरूक करते हुए शपथ भी दिलाई गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि जिसका मुख्य उद्देश्य उनको मतदाता के प्रति जागरूक करना, मतदान के महत्व को बताना एवं मतदान के लिए प्रेरित करना है। यह भी बताया गया कि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का आवश्यक रूप में उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में मतदाता के प्रति जागरूक करते हुए मताधिकार एवं महत्व को बताया गया कि भारत लोकतांत्रिक देश है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए मतदान अवश्य करें। क्योंकि मतदान हमारा अधिकार ही नही बल्कि कर्तव्य भी है। जिसका उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। सही व्यक्ति का चुनाव कर हम देश व समाज का भविष्य तय कर सकते है। एक-एक मत बहुमूल्य है, इसलिए मतदान का उपयोग किसी के बहकावे या लालच में आये बिना सही व्यक्ति के चुनाव में करना चाहिए। कार्यक्रम में जिले के समस्त परियोजनाओं से विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं जिसमें महिला प्रतिभागियों ने बढ़चढ कर हिस्सा लिया।

स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है घर-घर से

जांजगीर-चांपा /

झस्वच्छ मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामो को खुले में शौच मुक्त का स्थायित्व एवं स्वच्छ वातावरण बनाये रखने हेतु फेस-2 प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के घर से निकलने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित निपटान हेतु ग्राम पंचायत में शेड, नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट टैंक का निर्माण कर ग्रामो में सक्रिय स्व-सहायता समूह को संलग्न कर अपशिष्ट संग्रहण किया जाना है।

कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के निर्देशन में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ग्रामों को स्वच्छ बनाये रखने हेतु जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत दर्री दहिदा, सिउड़, जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत नवापारा-ब, दहकोनी, जनपद पंचायत पामगढ़ के ग्राम पंचायत खोरसी, तनौद और जनपद पंचायत अकलतरा के ग्राम पंचायत पिपरसत्ती, पकरिया, खोड, कटनई में आज ग्राम पंचायत के सक्रिय स्व-सहायता समूह द्वारा घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गोकुल रावटे द्वारा सभी ग्रामों में स्व-सहायता समूह को संलग्न कर घर-घर से निकलने वाले अपशिष्ट का उचित निपटान हेतु कचरा संग्रहण का कार्य कराये जाने के लिए जिले की सभी जनपद पंचायत को निर्देश दिये है।

साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय –राजेश्री महन्त

नवनिर्मित गुरु कबीर कुटी का भव्य उद्घाटन एवं संत समागम भंडारा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

ग्राम मचंगोढा, छोटे गंतुली ,सारंगढ़ में नवनिर्मित गुरु कबीर कुटी का उद्घाटन संत समागम भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कबीर आश्रम खरसिया से पधारे हुए सुधाकर दास शास्त्री जी ने की। इस अवसर पर कबीर साहेब के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित की गई। अतिथियों का स्वागत साल श्री फल एवं पुष्प माला से किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित स्रोताओं को अपना आशीर्वचन प्रदान करते हुए राजेश्री महन्त जी महाराज ने कहा कि- छत्तीसगढ़ राज्य में जहां कहीं भी कबीर संप्रदाय का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें यदि मुझे निमंत्रण प्राप्त होता है तो मैं यह निरंतर प्रयत्न करता हूं कि समय निकालकर उसमें उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हो, यहां भी आप लोगों ने याद किया था मैं आप सबके बीच में हूं। कुछ दिन पहले ही ग्राम तौलीपाली के कार्यक्रम में आप सभी से भेंट मुलाकात हुई थी, कबीर साहब स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे और मैं जिस संस्थान की सेवा करता हूं वह भी स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज से संबंधित है इसीलिए आप लोगों के कार्यक्रम में कुछ क्षण के लिए सही लेकिन उपस्थित होता ही हूं। कबीर साहब ने कहा है -साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूंखा न रहूं, साधु न भूंखा जाय।। हमें भी अपने जीवन में उनके इन विचारों को आत्मसात करनी चाहिए। लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष शास्त्री जी ने कहा कि -राजेश्री महन्त जी महाराज कोई सामान्य हस्ती नहीं हैं। वे बहुत बड़े मठ के पीठाधीश्वर हैं। श्री दूधाधारी मठ को लोग दूर-दूर तक जानते हैं और श्री शिवरीनारायण मठ हमारा तीर्थ स्थल है। इतने बड़े स्थान के मलिक होते हुए भी वे बड़ी सहजता से सामान्य आग्रह पर ही हम सभी के बीच उपस्थित हो जाते हैं यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। इतनी सरलता, इतनी सज्जनता परमात्मा ने इन्हें प्रदान की है। इस अवसर पर साहेब कन्हैया दास, महेश्वर दास, रोहित दास, हनुमान दास, ज्ञानेश्वर दास, कार्यक्रम के आयोजक सैनिक दास जी सहित अनेक संत महात्मा मंचासीन थे। राजेश्री महन्त जी महाराज के साथ इस कार्यक्रम में ठाकुर कमलेश सिंह एवं मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव विशेष रूप से सम्मिलित हुए। अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर विदाई दी गई।

आईटी और आईटी आधारित अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए छत्तीसगढ़ में भविष्य बहुत उज्ज्वलः मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय तथा मंत्री चौधरी ने दो आईटी कम्पनियों को संचालन हेतु सौंपा बिल्ट-अप एरिया आवंटन आदेश

- राज्य शासन राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर के योगदान को बढ़ाने के लिए कटिबद्धः ओपी चौधरी
- नवा रायपुर में 90 हजार वर्ग फीट बिल्ट-अप एरिया में काम करेंगी दो कंपनियां, 2200 युवाओं को मिलेगा रोजगार
- सीबीडी में आईटी इकाईयों के संचालन के लिए 2.80 लाख वर्गफीट बिल्ट-अप एरिया चिन्हांकित
- 10,000 कुशल रोजगार अवसरों का होगा सृजन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज दो आईटी कंपनियों मेसर्स स्क्वेयर बिजनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद एवं मेसर्स रेडिकल माइंड्स टेक्नॉलाजिस प्राइवेट लिमिटेड को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90 हजार वर्गफीट बिल्ट-अप एरिया का आबंटन आदेश सौपा। ये कंपनियां आईटी इकाईयों की स्थापना तथा संचालन करेंगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आईटी कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि नवा रायपुर को हम इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं।यहां बड़े पैमाने पर सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने की पहल राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए हम नया रायपुर में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी कर रहे हैं तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अधोसंरचना चाहिए। नवा रायपुर की संकल्पना के वक्त ही इसकी तैयारी कर ली गई थी और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों के अनुरूप उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम हैदराबाद और बंगलूरू की तर्ज पर नवा रायपुर में आईटी और आईटी पर आधारित अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे।इसके लिए हम इन उद्योगों को फर्निश्ड बिल्डअप स्पेस दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज दो कंपनियों स्क्वायर बिजनेस सर्विस हैदराबाद तथा रेडिकल माइंड्स टेक्नालाजी प्राइवेट लिमिटेड को 90 हजार वर्गफीड बिल्टअप एरिया दे रहे हैं। इससे 2200 कुशल रोजगार सृजन हो सकेगा।अभी अन्य कंपनियों से भी हमारी चर्चा चल रही है और लगभग 1 लाख 60 हजार वर्ग फीट में इकाइयों के संचालन के लिए आवेदन अपेक्षित हैं। इससे लगभग 3800 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इन आईटी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के लिए उचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण समन्वय कर रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उच्च स्तर की तकनीकी संस्थाएं हैं उसके चलते आईटी और आईटी आधारित अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए छत्तीसगढ़ में भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवा रायपुर में काम करने के बढ़िया वातावरण से निश्चित रूप से ही यह कर्मचारियों के लिए बहुत बेहतर कार्यक्षेत्र साबित होगा और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी।

इस मौके पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा की मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित किये जाने के संकल्प से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्विस सेक्टर उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु अनुकूल नीति एवं परिस्थितियों का समग्र विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा की राज्य शासन राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर के योगदान को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। सर्विस सेक्टर की सहायता से राज्य की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा की इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार, बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर अटल नगर में आईटी हब की स्थापना करने जा रही है, जिसके प्रथम चरण में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा छ्क्ष्छ, सेक्टर 21 में निर्मित रिटेल तथा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगभग 2,80,000 वर्ग फुट पर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों को फर्निश्ड बिल्टअप का आबंटन किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के युवाओं हेतु लगभग 10,000 कुशल रोजगार का सृजन अपेक्षित है, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न तकनीकी शिक्षा संस्थानों से आईटी कंपनियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय और वित्त मंत्री चौधरी की मंशा के अनुरूप नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, इसी क्रम में सर्विस सेक्टर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति एवं परिस्थितियां समग्र रूप से निर्मित की गई हैं, ताकि आईटी कंपनियां नवा रायपुर में अपनी इकाईयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने हेतु आईटी कंपनियों को आकर्षक दर तथा शर्तों पर फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस आईटी-आईटीज इकाई स्थापित करने के लिए आबंटित किया जा रहा है। प्रदेश में युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आईटी-आईटीज कंपनियों को प्रदेश के विभिन्न तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों से भी जोड़ा जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आईटी-आईटीज कंपनियों में कार्यरत युवाओं को उचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से समन्वय भी स्थापित किया गया है।

नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-21 में प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिला रिटेल काम्प्लेक्स तथा कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। इस बहुमंजिला काम्प्लेक्स में आईटी-आईटीज कंपनियों को आबंटन हेतु लगभग 2 लाख 80 हजार वर्गफीट बिल्ट-अप क्षेत्रफल चिन्हांकित किया गया है। जिसमें आईटी-आईटीज संबंधित कार्यालयों के संचालन से लगभग 10,000 कुशल रोजगार अवसरों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजन होगा। `इस मौके पर राज्यसभा सांसद देवेन्द्र बहादुर सिंह, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्योंकि अपने हाथों में अपनेपन का जादू होता है...

मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने अपने जन्मदिन पर आयोजित न्योता भोज में अपने हाथों से बनी खीर बच्चों को परोसी

सीएम मैडम के जन्मदिन पर बच्चों ने भी खूब मस्ती, मैडम के गालों में लगाया केक

रायपुर। अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित न्योता भोज में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने अपने हाथों से बनी खीर और केक बच्चों को खिलाई और उन्हें ढेर सारा स्नेह दिया। न्योता भोज का आयोजन सरदार प्रीतम सिंह सैनी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला श्यामनगर में और शासकीय बालिका गृह खम्हारडीह में किया गया। उन्होंने अपने परिवार जनों और बच्चों के साथ न्योता भोज भी किया।

इस मौके पर श्रीमती साय ने बच्चों से पूछा कि खीर कैसी बनी है। बच्चों ने बताया कि खीर बहुत अच्छी बनी है। उन्होंने बच्चों को बताया कि अपने जन्मदिन पर हम लोग हमेशा खीर बनाते हैं। मेरे बच्चों को भी खीर बहुत प्रिय है। आप सब बहुत प्यारे बच्चे हैं इसलिए आपके लिए भी अपने जन्मदिन पर आज खीर बनाकर लाई हूं। कौशल्या साय ने बच्चों से पढ़ाई लिखाई और बच्चों की छोटी-छोटी शरारतों के बारे में ढेर सारी बातें की। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों से भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा की।

कौशल्या साय ने चर्चा में बताया कि उन्हें साय जी ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान संचालित कर रहे हैं। यह बहुत सुंदर अभियान है। इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने सबसे आग्रह किया है कि अपना जन्मदिन और जीवन के खास अवसरों को स्कूली बच्चों के साथ मनाएं। वे बच्चों को भोजन कराएं और स्वयं बच्चों के साथ भोजन करें।

जब साय जी यह बता रहे थे, उसी समय मैंने निश्चय किया था कि मैं अपना जन्मदिन स्कूली बच्चों के साथ मनाऊंगी। जिस तरह से मैं हर साल अपने बच्चों के जन्मदिन पर खीर बनती हूं। उसी तरह से इस बार भी मैं अपने हाथों से खीर तैयार करूंगी और स्कूली बच्चों को खिलाऊंगी। आज बच्चों ने बहुत रुचि से खीर खाई। यह मेरा सौभाग्य है कि उन्हें मेरे हाथों की बनाई हुई खीर पसंद आई है। आज मेरा जन्मदिन सफल हुआ। उन्होंने कहा कि न्योता भोज बहुत सुंदर आयोजन है। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे छोटे छोटे प्यारे से बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है।

बच्चे बहुत रुचि से पकवान खाते हैं। उन्हें बहुत रुचि से खाना खाते देखकर बहुत अच्छा लगता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के पश्चात छत्तीसगढ़ में लगातार जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक न्योता भोज कर रहे हैं। आज कौशल्या साय का जन्मदिन है और उन्होंने भी इसे न्योता भोज के रूप में मनाया।

शुभ मौके पर खीर खिलाने की परंपरा वेदों से जुड़ी

भारतीय और छत्तीसगढ़ की परंपरा में जन्मदिन के अवसर पर खीर बनाई जाती है। लोग जन्मदिन में खीर खिलाकर मुंह मीठा कराते हैं। यह हमारी सनातन परंपरा है। जब भी कोई शुभ मौका होता है तो मुंह मीठा कराया जाता है। वैदिक काल से ही इस परंपरा की शुरुआत हुई। वेदों में खीर को क्षीरपाकमोदनम भी कहा गया है। खीर का इतना महत्व है कि अनुश्रुति है कि माता गंगा धरती पर सप्तऋषियों के आशीर्वाद युक्त मंगल खीर लेकर उतरी हैं।

हितग्राही मूलक योजनाओं को अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचाना करें सुनिश्चितः बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। शिक्षा एवं नारायणपुर जिले के प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल नारायणपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। मंत्री अग्रवाल ने जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर यह निर्देश दिया कि केन्द्र एवं राज्य शासन के फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन त्वरित गति से करते हुए इसे अंतिम पंक्ति के हितग्राहियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने बैठक में सभी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति का समीक्षा लेते हुए कहा कि जिले में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधा और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता से जल्द पूर्ण करें। मंत्री श्री अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जो स्कूल भवन और बाउंड्रीवाल विहीन है उनका सर्वे कराकर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना की जानकारी लेते हुए कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले के एक भी पात्र बहने इस योजना से वंचित न रहे। यह योजना सतत प्रक्रियाधीन रहेगी, उन्होंने कहा कि बेटी की विवाह के तुरंत बाद उसके आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए ऑनलाईन पंजीयन कराने का निर्देश दिए।

मंत्री अग्रवाल ने कृषि विभाग की समीक्षा में जिले के किसानों की धान बोनस राशि अंतरण की जानकारी लेते हुए सहकारिता विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन किसानों का बोनस राशि अब तक उनके खाते में अंतरण नही हुई हैं उनका एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि अप्रारंभ प्रधानमंत्री आवास को 15 दिवस के भीतर प्रारंभ कराएं, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में 412 गांव है, जिन गांवों में नल जल योजना प्रारंभ नहीं हुई है, वहां कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उद्यनिकी विभाग द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी लेते हुए जिले को अलग पहचान बनाने के लिए लीची और चीकू जैसी बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने की बात कही। राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री ने सड़क निर्माण कार्य की जानकारी लेकर बरसात के पूर्व सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिये। इसी प्रकार सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण विभाग और जनपद पंचायत विभाग के कार्यो का समीक्षा कर हितग्राही मूलक कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने निर्देशित किया।

छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वस्पर्शी मॉडल

आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन

राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने अयोध्या स्थित भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरु की। राज्य में राजिम कुंभ (कल्प) का भव्य आयोजन पुनः शुरु कर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे वैश्विक पहचान दी है। इसी तरह धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पांच शक्तिपीठों को विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 हजार किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। राज्य की रामायण मंडलियों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के साथ बस्तर दशहरे को 50 लाख, चित्रकोट के लिए 10 लाख की जगह 25 लाख रुपये, रामाराम मेले के लिए 15 लाख रुपये तथा गोंचा पर्व के लिए 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को इसी बात से परखा जा सकता है कि सरकार के गठन के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहली कैबिनेट में विष्णु देव साय सरकार ने 18 लाख 12,743 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया। योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का भी प्रावधान किया गया। वर्तमान में लगभग 15 लाख आवास के निर्माण को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी मॉडल देखने को मिल रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति

विष्णु देव साय सरकार एक ओर सुशासन की दिशा में नीतिगत कदम उठा रही है, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अमल में ला रही है। पूर्ववर्ती सरकार में हुए पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। साथ ही EWO द्वारा भी इस घोटाले में जांच की जाएगी है। कोयला और शराब घोटाले में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस तरह सरकार भ्रष्टाचार ख़त्म करने का प्रयास कर रही है।

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वय पर जोर

सुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। पं.दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय का आधार बताया है। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। यह विभाग राज्य में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन करेगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरु किया गया।

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का अंत्योदय

पं.दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय का आधार बताया है। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। यह विभाग राज्य में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन करेगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरु किया गया।

विकास के 10 स्तंभों की संकल्पना

विष्णु देव साय सरकार ने अपने पहले बजट में छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक ले जाने का रोडमैप प्रस्तुत किया है। 1 नवंबर 2024 को राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सरकार के विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करेगी। इसमें 2047 तक छत्तीसगढ़ की तरक्की की कार्ययोजना का विस्तृत वर्णन होगा। राज्य सरकार ने बजट में प्रदेश के अर्थतंत्र को गति देने के दस स्तंभ चिन्हित किए हैं।

अर्थतंत्र को गति देने के दस स्तंभ

1. ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था
2. तकनीक आधारित सुधार व सुशासन
3. आधिकारिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाना
4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन
5. सेवा क्षेत्र को बढ़ावा
6. निजी निवेश
7. बस्तर-सरगुजा की ओर देखो नीति
8. डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स का विकास
9. छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रोत्साहन
10. योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन

"अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047"

विजन डॉक्यूमेंट में राज्य हेतु संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास,GYAN आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनों का प्रभावी उपयोग, रिन्यूवेबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टैक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

विष्णु देव सरकार... 13 दिसंबर को ली शपथ और छत्तीसगढ़ में चल पड़ा विकास का सिलसिला

13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में खुशियों का नया सूर्योदय हुआ। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट के शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश में विकास का सिलसिला चल पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णयों से विष्णुदेव साय सरकार ने सुशासन को नया आयाम दिया है। किसान, युवा, महिला, गरीब, आदिवासी सहित सभी तबकों तक विकास की बयार पहुंच रही है।

मोदी की गारंटी
सुशासन के तीन माह

छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
- डिग्री हासिल करने वाले 246 एमबीबीएस एवं 21 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति दे दी गई है। इनमें से पचास फीसदी की नियुक्ति बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए की गई है।
- स्वास्थ्य विभाग में 5 हजार से ज्यादा पदों पर पीएससी और व्यापम के जरिए भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
- एमबीबीएस एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर नियुक्ति देने की घोषणा की गई है।
- कोल परिवहन के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली - खनिज संसाधन से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली लागू की गई है।
- नियद नेल्लानार योजना (बस्तर के लिए) बस्तर संभाग के नक्सल पीड़ित क्षेत्र में स्थापित 14 नये कैंपों में नवाचार के रुप में इसके आसपास के 5 ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास की कार्यवाही की जाएगी।
- कॉलेज के विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना ट्रैवल एलाउंस अगले शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना ट्रैवल एलाउंस मिलेगा।
- संस्कृत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का संकल्प।
- आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में इसी सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी।
- 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी अगले शिक्षा सत्र में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- सभी जिला मुख्यालयों में एम्स की तर्ज पर उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना का निर्णय।

युवा हितैषी सरकार

प्रदेश के युवाओं को शासकीय भर्तियों में निष्पक्ष और पारदर्शिता से युक्त परीक्षा का वातावरण मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इससे भर्ती परीक्षाओं में न सिर्फ युवाओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि परिश्रम से वह अपने सपनों की उड़ान को पूरी कर सकेंगे। सरकार के गठन के पहले महीने में ही विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर तथा अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

आतंकवाद, नक्सलवाद और चरमपंथ पर ठोस प्रहार

छत्तीसगढ़ सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और चरमंथ को समूल नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर स्टेट इनवेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जा रहा है। यह एजेंसी आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवादी मामलों की प्रभावी और त्वरित जांच करेगी। इसके लिए एसआईए एनआईए के साथ समन्वय स्थापित करने वाली राज्य की मॉडल एजेंसी होगी। नक्सल प्रभावित गांव के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को नियद नेल्लानार योजना शुरु की गई है। इस योजना के जरिए सुदूर नक्सल प्रभावित गांव में 24 योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित गांव में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं। सुकमा के पूवर्ती समेत अन्य स्थानों पर यह पुलिस कैंप कानून व्यवस्था को मजबूती देने के साथ सुशासन के प्रकल्प बनकर उभरे हैं।

भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष के टेक्स जमा कराना होगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब राज्य की नवनिर्वाचित सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का पहला डिजिटल बजट पेश किया। इससे शासन एवं प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल अनुप्रयोग के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे। राज्य में कोयले के परिवहन हेतु परमिट और स्वीकृति व्यवस्था मैन्युअल होने से पूर्व की सरकार के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ऐसे में विष्णु देव साय सरकार ने तत्काल इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मिसाल पेश की है। प्रदेश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये, पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपये, एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये और अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

विगत 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में 'महतारी वंदन योजना' की पहले किस्त की राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने माता- बहनों को शुभकामनाएं दीं।

'महतारी वंदन' योजना से हो रहा महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण विष्णु देव साय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के इतिहास में 12 मार्च 2024 की तारीख महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 1,000 रुपये की पहली किश्त जारी की गई। विष्णु देव साय सरकार हर साल 12 हजार रुपये महिलाओं के खाते में जमा करेगी। भ्रष्टाचार के बिना हितग्राहियों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ डीबीटी का सबसे बेहतरीन उपयोग करने वाला राज्य बन चुका है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंगविभेद, असमानता ख़त्म करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है।

महतारी वंदन हेल्पलाइन- 0771-2220006 / 0771-6637711

किसानों के चेहरे पर खुशी... छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य

छत्तीसगढ़ में धान की फसल यहां के किसानों के लिए तरक्की का आधार है। विष्णु देव साय सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की मोदी की गारंटी को पूरा कर देश में किसानों को धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने का कीर्तिमान रच दिया है। किसानों के खाते में सीधे नगद लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए पैसा भेजा जा रहा है। खरीफ सीजन 2023 में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ (3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से) 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। इस तरह छत्तीसगढ़

ने देश में धान की खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में 13 लाख किसानों के खाते में धान के दो वर्ष के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि 13,320 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 24.72 लाख से अधिक किसान विष्णु देव साय सरकार की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

R.O. No. 40024/35

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाउस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)